[Shri Jagjivan Ram]

There is little doubt in my mind that these recreational and cultural activities help in inculcating the spirit of comradieri and enthusiasm for joint and sustained efforts in their duties amongst the large family of railwaymen spread over the far flung corners of this vast country.

Conclusion

63. Once again I would like to place on record my appreciation of the sustained and creditable performance of railwaymen of all levels, particularly in executing the ardous task of implementing the Second Five Year Plan. The Third Five Year Plan, with problems of even larger dimensions, is not far away and I am sure that continued appreviation, goodwill and good wishes of every one will act as a stimulus to the railwaymen to tackle the bigger tasks ahead.

64. I am grateful, Sir, to you and the House for the patient hearing I have been given, and for the support and encouragement I have been receiving in ample measure from the Parliament, the general public and from State Governments.

13.4 hrs.

MOTION ON ADDRESS BY THE PRESIDENT—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri T. N. Viswanatha Reddy and seconded by Shri Ansar Harvani on the 15th February, 1960, namely:

> "That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on the 8th February, 1960."

Shri Ram Krishna Gupta will continue his speech.

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : जैसा कि मैंने कल कहा था, जहांतक कि फिजिकल टारगेट्स का ताल्लुक है वे भी पूरे नहीं हो सके। उस के बारे में मैंने इस हाउस में एक सवाल भी किया था जिसका जवाब देते हुए बतलाया गया :

> "A net rise of about ten per cent has been recorded by the end of 1958-59, as against 25 per cent."

इसी तरह से फूड के बारे में भी कहा गया मैं यह इस लिए कह रहा हूं कि जो टारगेट मुकर्रर किये जायें वे पूरे हों। यही हाल लैंड रिफ़ार्म और कोआपरेटिव फ़ार्मिंग का है। लैंड रिफ़ार्म के बारे में जो हमारी पालिसी है, जो प्रोग्राम है, इतने साल गुज़र चुके, मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि वह अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्टेट ट्रेडिंग के बारे में भी जो स्कीम बनायी गयी थी उसके मुताल्लिक पिछले दिनों अखबारों में यह खबर थी कि उसको छोड़ा जा रहा है। मैं ये तमाम बातें इसलिए हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि इसका आम पबलिक पर बुरा असर पड़ता है। हम जो भी प्रोग्राम बनाएं, हमारी जो भी पालिसी हो,हमें उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब हम थर्ड फ़ाइव इयर प्लान तैयार करने जा रहे हैं तो हमें इन तमाम बातों की तरफ़ ध्यान देना चाहिए। ये तमाम चीजें क्यों पूरी नहीं होतीं ? जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है, मेरा यह ख्याल है कि हमारा जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वह इस के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। जो प्रोग्राम वगैरह बनाया जाता है उसके लिए जो फंड की जरूरत पड़ती है उसको सैंक्शन करने में काफ़ी देरी होती है। इसलिए वह तमाम स्कीमें वक्त के अन्दर पूरी नहीं होती। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जो मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज हैं,खास तौर पर जो डेवेलपमेंट के काम को करती हैं, उनके अन्दर जितना कोआर्डिनेशन

और कोआपरेशन होना चाहिये वह नहीं होता । इसके लिए सब से ज्यादा जीती जागती मिसाल हमारे फारमर फ़ूड मिनिस्टर की तकरीर है । इससे ज्यादा मैं इसके लिए क्या सबूत दे सकता हूं । इस तरफ़ भी ध्यान देने की जरूरत है और हमें यह पूरी कोशिश करनी चाहिये कि जो मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज हैं उनके अन्दर फूड कोआर्डिनेशन औ कोआपेरेशन होना चाहिए ताकि हमारा डेवलपमेंट का काम सफर न करे ।

इसके बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मिसयूज और वेस्टेज हो रहा है उसको भी रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जो रुपया किसी खास मकसद के लिए सैंक्शन किया जाता है अगर उसको ठीक तरीके से यूटीलाइज किया जाए तो काफी फायदा हो सकता है । खुराक का जो मसला है वह इसीलिए हल नहीं हो रहा है । इस किस्म की हजारों मिसालें मिल सकती हैं । मैं गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को इसके लिए परसनली जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहता लेकिन मैं यह चीज जरूर चाहता हूं कि जो रकम दी जाए उसको प्रापरली यूटीलाइज किया जाए ताकि वह मिसयूज न हो सके ।

पिछले दिनों सीड फार्मों के लिए पंजाब गवर्नमेंट को काफी रुपया दिया गया । इस किस्म की वहां से काफी शिकायतें आती हैं कि जो रुपया दिया गया वह ठीक तरह से यूटीलाइज नहीं हुआ और जो रुपया दिया गया उसका, जिन लोगों के हाथ में ताकत थी, उन्होंने अपनी जमीन गवर्नमेंट को बेच कर मिसयूज किया । ये तमाम चीजें हैं कि जिनके लिए एन्क्वायरी की जरूरत है और मैं खास तौर पर इस बात के लिए जोर दूंगा कि जो रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदद के लिए दिया जाए उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए । मेरी तो यह तजवीज है कि एक ऐसी कमेटी मुकर्रर की जाए जो तमाम स्टेट्स का दौरा करे और जो रुपया दिया गया है उसकी पूरी जांच हो कि वह किस हद तक यूटीलाइज हुआ है और किस हद तक मिसयूज हुआ है ताकि इस किस्म की चीजें आयन्दा न हो सकें ।

इसी तरह जहांतक कोआर्डिनेशन का सवाल है उसके बारे में तो मैं सिर्फ एक ही मिसाल देना चाहता हूं । पिछले दिनों हाउस में भी इस सवाल का जिक्र आया था । इर्रीगेशन की जो स्कीम बनायी गयी और जो प्रोग्राम बनाया गया और जिस इलाके को फैसिलिटी दी गई उस का मिनिस्टर आफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने फायदा नहीं उठाया और उन फैसिलिटीज को यटीलाइज नहीं कर सके । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ है । मुझे पूरा विश्वास है कि जो ग्रांट दी जाती है अगर उसको प्रापर्ली यूटीलाइज किया जाये और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में पूरा कोआपरेशन और कोआर्डिनेशन हो तो हमारा खुराक का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाए और हमें दूसरे मुल्कों से अनाज इम्पोर्ट न करना पड़े । रिवाड़ी के पास दो तीन ट्यूब वैल लगाये गए । उनको लगाए हुए दो तीन साल हो गए और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी तक उनको काम में लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गयी और वह बेकार पड़े हैं । इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा ।

इस के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम बनाया जाय और जो स्कीम तैयार की जाय वह ऐसे ढंग से होनी चाहिए कि उस से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो । पंजाब के लिए १२७८ ट्यूब वैल्स का प्रोग्राम बनाया गया । यह मामला पंजाब की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने आया । और पब्लिक एकाउंटस कमेटी के मेम्बरों ने यह सवाल उठाया कि इस से कितना फायदा हुआ है, और यह जाहिर किया गया कि इन तमाम ट्यूब वैल्स से कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे काफी

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

अर्से तक बेकार पड़े रहे । उस का कारण यह बतलाया गया कि वह ऐसे इलाके में लगाए गये थे जोकि इर्रीगेटेड एरिया था । जो जमीन इर्रीगेशन के जरिए सैराब की जाती है उस के रेट कम हैं । इसलिए किसानों ने ट्यूबवैल्स के जरिए पानी लेने से इन्कार कर दिया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिये था कि उस इलाके के बजाये ऐसे इलाके में ट्यूबवैल लगाये जाते जोकि इर्रीगेटेड नहीं था और जहां के किसान उस पानी को आसानी से इस्तेमाल करते । एक तरफ तो यह हालत है कि जहां पानी की इफरात है वहां ट्यूबवैल लगाये जाते हैं और इस से पैदावार को नुकसान होता है, और दूसरी तरफ यह हालत है कि पानी की इतनी कमी है कि पीने के पानी के लिए भी लोग तड़पते हैं । इस के बारे में जो एक्सप्लेनेशन वहां के चीफ इंजीनियर ने दिया वह भी मैं हाउस को सुनाना चाहता हूं और आप सुन कर अन्दाजा लगा सकते हैं कि कैसा जवाब था । उन्होंने यह जवाब दिया था :

"It is admitted that this scheme was taken up in haste on account of the aid given by the Government of India."

इस का मतलब यह हुआ कि जो एड गवर्नमेंट आफ इंडिया से दी जाय उस के बारे में विचार करने की कुछ जरूरत नहीं । उस के बारे में प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं । इसलिए मैं ने यह सवाल हाउस के सामने रखा कि हमें इस बारे में पूरा ध्यान देना चाहिये और हमारे प्रोग्राम इस किस्म के होने चाहियें कि हम जो एड स्टेट गवर्नमेंट्स को दें, वह पूरे तरीके से यूटीलाइज हो और उस से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ।

इस के बाद मैं थोड़ा सा यह भी कहना चाहता हूं जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि हम जो थर्ड फाइव इयर प्लान बनावें उस में हमें इन तमाम बातों को सोचना चाहिये ताकि हमारे लिए फारिन एक्सचेंज की कमी न हो और हमारी स्कीमें पूरे तरीके से कामयाब हों । और यह बात इसलिए भी जरूरी है कि जिस से लोगों पर इस का अच्छा असर पड़े । मेरा ख्याल तो यह है कि प्लान की कामयाबी के लिए रुपये की इतनी जरूरत नहीं, डालर की इतनी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत लोगों के को-आपरेशन और मदद की है और वह को-आपरेशन सरकार को मिल नहीं सकता, जब तक कि लोग यह महसूस नहीं करेंगे कि जो प्लान या स्कीम बनाई जायगी, उस से हमारा—आम जनता का—फ़ायदा होगा और जो लोग ताकत में हैं, वे उस को मिसयूज़ नहीं करेंगे और कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठायेंगे । इस की सब से ज्यादा जरूरत है । इसलिए मैं अपील करूंगा कि जो भी प्लान बने, उस में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाये । हमारे देश में मैन पावर की कमी नहीं है । मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि जब दुनिया के किसी भी बड़े देश में पहले प्लान बनी, तो वहां रुपया कहां से आया । मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां के लोगों ने फ़िजिकल प्लान बनाई, मैन पावर को यूटिलाइज किया, वहां के लोगों में जोश पैदा किया गया और उन की स्कीम कामयाब हुई और आज वे इस हालत में हैं कि वे तमाम दुनिया को रुपया दे कर मदद कर सकते हैं । आज हमारे लिए भी इस बात की सब से ज्यादा जरूरत है और इसलिए इस तरफ़ पूरा ध्यान देना चाहिये ।

14 hrs.

हमें यह भी पूरी कोशिश करनी चाहिये कि जो हमारी प्लान हो, उस में अनडेवेलप्ड और बैकवर्ड एरियाज़ का खास तौर पर ख्याल रखा जाये । आज भी देश में बहुत सा ऐसा इलाका है, जोकि अनडेवेलप्ड और बैकवर्ड है । उस की तरक्की के लिए कदम उठाने की खास तौर पर जरूरत है । मेरी तो यह तजवीज़ है कि इस के लिए एक कमेटी

या कमीशन मुकर्रर किया जाय, जोकि ऐसे इलाकों का सर्वे करे और सैण्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस इलाके की मदद और तरक्की के लिए रुपया रिजर्व किया जाये, ताकि वह उस मक़सद के लिये काम आ सके । मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि कल भी हाउस के सामने यह सवाल आया कि पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं, जो यह सोचते हैं कि पंजाब के दो हिस्से किये जायें और जो हिन्दी स्पीकिंग इलाका है, उस को दिल्ली और यू० पी० के कुछ हिस्से से मिला कर एक अलग स्टेट बनाई जाये । मैं आप को सही तौर पर कहता हूं कि अगर उस इलाके की तरक्की के लिये पूरी कोशिश की जाये तो यह समस्या बड़ी आसानी से हल हो सकती है । मैं पोलीटिकल पावर में बिलीव नहीं करता हूं । मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम में बिलीव करता हूं । अगर इस तरफ़ ध्यान न दिया गया, तो उस का नतीजा यह होगा कि जो लोग पोलीटिकल स्लोगन्ज में विश्वास करते हैं, जो लोग पोलीटिकल पावर में विश्वास करते हैं, वे वहां के लोगों को एक्सप्लायट करेंगे और ऐसे हालात पैदा करेंगे कि सरकार को बम्बई के बाद उस इलाके के लिये भी सोचना पड़ेगा कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया जाये । इस खतरे को रोकने का एक ही जरिया है और वह यह है कि उस इलाके की तरक्की के लिए पूरा ध्यान दिया जाये, उस इलाके को डेवेलप किया जाये और लोगों के दिलों को जीता जाये । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले दिनों रिजनल फारमूला बनाया गया । हो सकता है कि शायद कुछ दोस्त यह महसूस करें कि मैं उस की इसलिए मुखालफ़त करता हूं कि पंजाब के दो हिस्से हों । नहीं, मैं उस की इसलिए मुखालफ़त नहीं करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि पंजाब एक रहे और पंजाब के लोग मिल कर काम करें । उस फारमूले में मुझे जो अच्छी चीज नजर आई, वह यह थी कि तरक्की के जो काम होंगे उस में उस इलाके का पूरा हाथ होगा और उस की पूरी तरक्की होगी । लेकिन आज तीन चार साल के बाद मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि उस इलाके की हालत उसी तरह है और वहां के लोगों की तरक्की के लिए कोई खास कोशिश नहीं की जा रही है । सर्विसिज़ में यही हाल है और लैंजिस्लेचर और एगज़ैक्टिव पावर में भी यही हाल है । इसलिए मैं यह अपील करना चाहता हूं कि वह जो इलाका है, उस की तरक्की के लिए खास तौर पर इन्तज़ाम किया जाय और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह ख्याल रखना चाहिये कि जो पंजाब के हिस्से में रकम आये, उसे दोनों हिस्से के लिए अलग वक़्फ़ किया जाये, ताकि हर हिस्से के लोगों को तरक्की का मौका मिले और वे उन्नति कर सकें ।

जहां तक करप्शन का सवाल है, यह मामला भी काफ़ी ज़ोर से हाउस के सामने कई दिनों से आ रहा है । बहुत से दोस्तों की यह राय है कि करप्शन के बारे में ग़लत चार्जिज़ और स्वीपिंग रिमार्क्स लगाये जाते हैं, लेकिन मैं तो एक बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं । चाहे वे चार्जिज़ सीरियस हों, चाहे उन में सच्चाई हो, चाहे वे ग़लत हों, लेकिन उर्दू में एक कहावत है कि बद से बदनाम बुरा होता है, इसलिए हमें इस बात की तरफ़ पूरा ध्यान देना चाहिये । अगर वे ग़लत हैं, तो उन को कांट्राडिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिये । अगर उन में कोई सच्चाई है, तो उन की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिये । मैं किसी शख्स के बारे में कोई पर्सनल एलीगेशन लगाना नहीं चाहता । मैं तो यह चाहता हूं कि जो भी इस किस्म की बातें आयें, हमें उन की तरफ़ पूरा ध्यान देना चाहिये । यह कोई ज़रूरी नहीं कि ट्राइब्यूनल के जरिये ही उन नुक्सों को दूर करने की कोशिश की जाये और भी कई तरीके हैं । मैं यह बात खास तौर तो इस लिए कहता हूं कि अखबारों में इस किस्म के बहुत से शदीद इल्जामात आते हैं और

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

उन की कांट्राडिक्शन नहीं होती, जिस से लोग यह सोचते हैं कि शायद इस में कोई सच्चाई हो । कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां मिनिस्टर के लड़के ने ढाई करोड़ रुपये का फलां काम का ठेका लिया, फलां मिनिस्टर ने यह किया, फलां ने वह किया । हो सकता है कि इस में सच्चाई न हो, लेकिन इन चीजों की तरफ़ बिल्कुल ध्यान न देना, इगनोर करना भी एक खतरनाक बात है । मैं यह अपील करूंगा कि हमें इस तरफ़ भी पूरा ध्यान देना चाहिये ।

14.04 hrs.

[SHRI GORAY *in the Chair.*]

कल मेरे दोस्त, चौ० रणवीर सिंह, ने जो कि मेरे पंजाब के साथी हैं, अपनी स्पीच में यह कहा कि राम कृष्ण को शायद किसी शख्स से या उस के लड़के से कुछ जाती रंजिश है, इसलिए वह बार बार पंजाब का मामला यहां उठाने की कोशिश करते हैं । यह एक बड़ी सीरियस एलीगेशन है । इसलिये मैं इस के बारे में दो चार मिनट ; सिर्फ़ इतना ही कहूंगा कि . . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के लिए सिर्फ़ दो मिनट बाकी हैं, चार नहीं ।

Shri Tyagi (Dehra Dun): If a gentleman has made a personal allegation against him, he must be given the right to explain himself.

Mr. Chairman: Within four minutes, I hope.

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ कल कहा गया, उस के मुताल्लिक तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अपने बारे में मैं इतना कहने के लिये तैयार हूं कि अगर इस किस्म की कोई बात साबित हो जाये कि कोई मेरी उन से जाती अदावत थी, या मैं ने उन के आगे अपनी जिन्दगी में आज तक कोई जाती रिक्वेस्ट की, तो मैं इस हाउस से इस्तीफ़ा देने के लिये तैयार हूं । बल्कि मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब इन तमाम मामलों की एन्क्वायरी करें । लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि ख्वाह मैं हूं, ख्वाह वह हों, ख्वाह कोई हो, जिस के हाथ में ताकत हो, जो लोगों से डील करे, तो उस के लिए लोगों से डील करने के लिए एक स्टैण्डर्ड होना चाहिये, पब्लिक से डील करने का एक स्टैण्डर्ड होना चाहिये, मिनिस्टर से डील करने का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिये, पार्टी कोलीग्ज़ से किस स्टैंडर्ड से डील करना चाहिये, इस के लिए कोई न कोई तरीका ज़रूर होना चाहिये । इस तमाम मामले की एन्क्वायरी की जाये और एक मिनिमम स्टैण्डर्ड फिक्स किया जाय और यह मालूम किया जाय कि उस पर अमल होता है या नहीं, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं । मेरा इख्तिलाफ़ जाती इख्तिलाफ़ नहीं । मैं चाहता हूं कि ज़ो भी प्रोग्राम बनाया जाये, जो भी पालिसी हमारी हो, उस को इम्प्लीमेंट किया जाये । लैंड रिफ़ार्म्ज़ का हमारा प्रोग्राम था, वह क्यों नहीं कामयाब हुआ, इस की एन्क्वायरी की जाये । जो ग्रांट्स दी जाती हैं, वे क्यों मिसयूज़ होती हैं, वे तमाम मामले हैं जिन में न कोई जाती सवाल है और न ही जाती सवाल पैदा हो सकता है जिन्हें कि आप को देखना चाहिये ।

Mr. Chairman: Acharya Kripalani.

Shri Tyagi: His party leader has already spoken, but Shrimati Kripalani was, on the other hand, trying to catch your eye.

Mr. Chairman: For me it is a difficult choice.

Acharya Kripalani (Sitamarhi): As I was absent from the House for the first two days of the discussion on the President's Address, I had no intention to speak on the Motion of Thanks at this late hour. Most of what was to be said has already been said by abler persons than myself. I will, therefore, be very brief.

I feel I cannot remain silent on the issues arising out of the last letter addressed by our Prime Minister to the Prime Minister of China and the note sent by our External Affairs Department to its Chinese counterpart. There may be nothing in the matter of dates of the two communications, but it is not usual to put a date on a communication while delivering it.

About the note I would say that I wish that the facts contained in it had been made public as soon as there were incursions in our territory on the Himalayan borders. This should have been done years ago. In that case, the public and the world at large would have better appreciated our position.

Another point that emerges from the note is that our trouble on the borders began, as I have always held, with the non-recognition of the independent status of Tibet. From the present note it is quite clear that Tibet was not only considered autonomous in its internal affairs, but also enjoyed a sovereign status. It could and did participate in international negotiations as an independent nation. On such occasions it enjoyed an equal status even with China without any protest from the latter, in spite of the so-called suzerainty. How then could India in all conscience recognise the armed conquest of this small internationally independent State, especially when our Prime Minister had often said that India would not be neutral where injustice and tyranny were involved? I am afraid we have let down a small state on our border to our own disadvantage.

The letter of the 5th instant invites the Chinese Prime Minister for a meeting next month on our soil. I am sorry I am constrained to say that it is not in consonance with our Prime Minister's earlier statements or the rejection of a similar offer from the Chinese Prime Minister made a few months before. Our Prime Minister has repeatedly said that there is no basis for a meeting at present. He had made it clear that before a meeting between the two Prime Ministers could be fruitful, it was necessary that the principles and the bases on which negotiations could be carried on must be first clarified. This point is further stressed in the note of the 12th instant, sent by our foreign office. Even from the President's Address, it is clear that at present there exists no basis for a fruitful meeting. It is also a little strange that our Prime Minister should have reiterated this position in emphatic terms in the Rajya Sabha when he had already sent the invitation. Having done so, he should have mentioned the fact at least in the Rajya Sabha, where the question was raised. It was not a secret communication. It was only a letter of invitation, the mention of which need not have waited for its receipt by the party concerned. Further, it is strange that in the President's Address, there was no mention of the invitation extended to the Chinese Prime Minister. Rather, the indication was that there was no basis for a meeting at present. One wonders if the President knew about the invitation. I feel that if he had known it, he could not have failed to mention such an important change of policy in his Address. I am afraid this puts the President in an awkward position before Parliament and the public. Also, it does not add to the dignity of our country that our Prime Minister should change his position so soon and so suddenly, without an explanation or even an excuse.

I also feel that it is not quite desirable to invite the Chinese Prime Minister to India for a conference at this stage. Our Prime Minister has assured him that he will be received as our 'honoured guest'. However, the people whose feelings and national interests have been injured may not respond as warmly to the visit as our Prime Minister would wish or expect. This, I am sure, will not be appreciated by our guest or by our Prime Minister. Our Prime Minister should have, therefore, thought better of it

[Acharya Kripalani]

before extending the invitation. After all, people in India, even though they love their Prime Minister, cannot be regimented to show respect to a guest who, in their eyes, has been instrumental in devising policies injurious to the integrity and honour of India. They would not have been so regimented even under foreign rule. Such things would be possible only in a totalitarian State.

The visit may even divide our people; one section may wish to give the Chinese Prime Minister a warm welcome; another may remain indifferent, if not hostile. This will produce divisions in our own ranks, which obviously will not be very profitable for the country.

I am sorry that I have to refer to another matter which may not be liked by the Prime Minister or the Defence Minister. Fortunately, there is no occasion for them to be angry with me, for they are not present here now. I am referring to a reported statement made by the Defence Minister. He is reported to have said at a students' meeting somewhere that we shall not yield an inch of our 'administered territories'. He is a master of the English language. He could not have used these words accidentally. As a matter of fact, such words do not come out of one's mouth without previous thought. If he was thinking of the NEFA area, he should have made his point clear. And, then what about Ladakh areas? People wonder if the words used represent the views of the Defence Minister or those of the Prime Minister and the party to which the Defence Minister happens to belong at present.

On a former occasion, the Prime Minister had said in the House that the Defence Minister represented his views and carried out his policies. At that time, I had pointed out that though this may be true, it was quite possible for a Minister, in his speech and actions, to give such a twist to the Prime Minister's views and instructions as to put them altogether out of shape. The Prime Minister's own utterances seem to run counter to the sentiments expressed by the Defence Minister. Is it that the Defence Minister wanted to familiarise the country with the idea that ultimately we may yield to the Chinese such of our territory as where we had established no administrative control or where not a blade of grass grows or where no human being can live, though the Chinese seem to be living there and prospering? Was the Defence Minister's statement meant to gauge public reaction to a proposition which is in contemplation somewhere? We would like to know what value can be attached to such utterances of the Defence Minister. It is such utterances as these that offend the people and rouse their apprehensions. I hope he will be more careful about what he says, so that the Prime Minister may not be obliged to defend him and explain the meaning of the words used and fight foul of the critics of the Defence Minister.

There is another delicate point which I would like to mention here. We are receiving economic aid both from the West and from Russia. We are friendly to both the countries. We are thankful for the help given. If, however, one side denounces the aid given by the other, from our soil, we are put, surely, in an awkward position. Both sides have a perfect right to criticise and even denounce each other, but not when they are our honoured guests and accept our hospitality. The laws of hospitality should induce some restraint on our guests, especially where such restraints are not violated by our honoured guests from the West.

Mr. Chairman: Now, Shrimati Sucheta Kripalani.

Shri Tyagi: She will teach him a lesson.

Shrimati Sucheta Kripalani (New Delhi): I am afraid I cannot compete

with the august speaker; I shall be at a very low level.

Shri Tyagi: She is the better half.

Shrimati Sucheta Kripalani: I am very happy to associate myself with this motion of thanks to the President for his excellent address. He has covered a very wide range of subjects. With the short time at my disposal, I can focus my attention to only a few points. I shall confine my remarks, therefore, in a limited way to some of our achievements in the industrial sphere and some of the major difficulties that we are facing today.

Shri Asoka Mehta (Muzaffarpur): What about the points raised by the previous speaker?

Shrimati Sucheta Kripalani: Those points will be answered by bigger people than myself.

An Hon. Member: By *Dada*.

Shrimati Sucheta Kripalani: The President, in his Address, has given us a picture of the industrial advance. It is an impressive record of achievement. No one can deny that the country has advanced fairly towards creating an industrial base on which the economy can be built up. I shall refer to only a few important industries. I shall take steel first. Steel production, which is the base of all industrial development, has, as you all know, gone up both in the public and the private sector. The production will be about 6 times more in 1962 as compared to 1949. Even today the full capacity has almost been installed. Our engineering industries, small scale industries and other industries were all suffering from steel shortage. In fact, the dip in our national income in 1957 was due to a certain extent to the shortage of steel and other raw materials. Now uninterrupted development of these industries and continuous growth of national income can be expected.

While referring to the steel industry, I think it is appropriate for me to suggest that a substantial part of the steel output should be allocated for better ploughs and other agricultural implements. We all acknowledge the importance of agriculture in our economy. But I find that we are swayed by the demands of capital goods industries. Therefore, in actual practice, steel becomes scarce for agricultural implements and for small industries. The test of the importance we attach to agriculture will be this allocation of steel.

I may also suggest that Government pay particular attention to the development of ancillary industries round the steel plants. The present tendency is to compress all workshops within the steel plants. This reflects a backward state of economy. Feeder industries not only provide employment for the people, but, contrary to the general belief, are also more economical for the steel plants.

To refer to a few other key industries, geological survey and exploration of oil has registered a good advance and to that extent our dependence on foreign countries for these commodities would be lessened. The machine tool factories both in the private and public sectors are making progress. A beginning has been made in the manufacture of electrical equipments including heavy electrical equipment. The Sindri Fertiliser Plant has gone into capacity production. Smaller factories have been started. I am glad to note that Shri S. K. Patil has given a good lead in starting medium size fertiliser factories in the States. In other spheres, as in irrigation and power, we have made a very good beginning. This record of achievements is something of which any nation can be proud.

But in spite of this impressive record of achievements in the industrial field, we find dissatisfaction and frustration in the country. This is due to the fact that we have not succeeded in translating these benefits in terms of raising the condition of the masses, specially at the level where relief is most needed. This leads to general discontent, criticism of Government

[Shrimati Sucheta Kripalani]

and even belittling of our achievements. It is creating not merely a psychological barrier but causing hindrance to our economic effort. It has also its impact on the administration. This was highlighted during the recent debate on the Report of the Pay Commission—two days back in the House. We have seen that under the pressure of the government servants, a Pay Commission was appointed. The recommendations came. Government are implementing them. The implication of the implementation would be an additional expenditure of Rs. 55 crores, according to the statement of the Finance Minister. In spite of all that, in spite of the sympathetic attitude of Government, in spite of their effort to raise the pay of Government servants, the little rise in salary that we have managed to give them has not satisfied them. There is criticism, there is discontent. It is due to the fact that the cost of living is so high that the little rise that they have got in the pay is of very value in terms of purchasing power.

Therefore, for the success of our development plans for the good of the country generally, it is absolutely necessary to lay stress on meeting the basic needs of the people, by which I mean food, cloth and housing. The essence of the problem today is how to combine development and stability, that is, how to hold the price line, specially of the essential commodities such as food and cloth.

Let us take the most important problem of food. Over and over again, this matter has come up before the House. Inspite of efforts on the part of the Government the price of food keeps on rising. It is not a commodity that people can do without. People cannot exist without food. Therefore, the price of food must be brought down. This year a strange phenomenon is in evidence. The 1958-59 production is higher; we have produced 73·5 million tons of foodgrains. But even with this higher production, there is scarcity in the market; there is steep rise in price. The wholesale price index does not reveal the extent of rise in consumer prices of food. The figure available is 4.4 per cent, but the retail price is much higher. The working class consumer price index figure for September 1959 was 7 per cent. higher than that of March 1959, that is, 7 per cent. rise in six months. It is becoming a crushing burden on the poor.

Therefore, the most important problem is how to hold the price line. I am afraid all Government efforts in this direction seem to have failed. They have not brought about the desired result. The real answer is, of course, increase in agricultural production which will help to ease not only the food situation but also the textile situation by the production of more raw cotton. I cannot say that Government were not aware of the problem, and that they did not take any steps. They tried to take some steps. Realising the need for stabilising food prices, they initiated certain policies and took some steps to check the rise in price.

These are the steps they took. First of all, they divided the country into food zones. Then maximum wholesale prices were fixed in certain States. Further, selective credit control was adopted by the Reserve Bank of India. The most important step was the introduction of an interim pattern of State trading. Unfortunately, the effect of all these steps was inflation rather than stabilisation. The effect was quite contrary to the desired objective.

Let us see how the State trading has functioned. Instead of becoming a measure to check the inflationary effect of deficit finance in the coming year, it has become the direct cause for rise in prices. I feel that the reason is that the prior conditions for starting State trading were not

fulfilled. State trading is difficult. The nation should have been prepared for it, and then it should have been launched. In China and other communist countries where there is State trading, they first controlled credit. Then they controlled farm units through co-operatives and then they launch State trading. Now, our country was not prepared in this way. Of course, I know we cannot adopt all those measures. But at the same time, we must realise that the problems of State trading in a deficit country are quite different from those in a surplus country.

So far we have seen State trading only in surplus countries under the democratic system. In other countres where State trading is enforced irrespective of their being surplus or deficit are the Communist countries but their administrative system is quite different from ours. They can enforce State trading even in a deficit condition ruthlessly, which we certainly cannot do. Now, if by State trading we mean merely buffer stock operation by Government, then the position is different. That can be done immediately. Under the present system, as a result of this State trading, as a result of the declaration of maximum price and with the 'wait and see' policy of the peasant, Government has become the buyer of the last resort. Therefore, State trading has not yielded the expected result. We have not been able to hold the price line and the prices continuously go on rising.

The other important step was the introduction of the zonal system. I shall say a few words about it. To my mind, the present zonal system is unscientific, because a correct and scientific zonal formation would have to cut across administrative boundaries. A correct and scientific zonal formation means the "marriage of surplus with deficit areas." This would have created administrative difficulties. Therefore, one could not have thought of that. The demand for smaller State-wise zones is also not quite right. Complete free trade is impossible unless free trade exists in other parts of the world. But at the same time, defective zones cannot help. In defective zones, thanks to the price differential, there is incentive to smuggling. Prices rise in the process of smuggling. The smugglers raise the prices by a multiple of the money they lose if they are detected. Therefore, we see the spectacle of sincere efforts on the part of Government to hold the price line, while the prices are rising all the time.

What is the solution? I am not an expert. I cannot suggest any solution. But I am offering a suggestion which can be given trial. We can try to cordon the bigger cities and at the same time make the rest of the country into one zone, that is, have free trade in the rest of the country, plus have buffer stock operation. Build up stocks both by import and by procurement in the good year. No attempts should be made to procure in the bad year. Fortunately for us, we had a good year last year, and for the coming year the crop forecasts are bright. So this is the time when we can build up a buffer stock. If we have sufficient buffer stock that will have a salutary effect in checking the profiteering psychology; and only then we may, perhaps, be able to hold the price line.

Now, I come to the next important commodity, cloth. Cloth price is now so high that consumer resistance has come to play. Is this rise justified? It is true that cotton output has fallen this year and the supply of cloth for domestic consumption is slightly lower than in the previous year, particularly, in dhotis and saris. But this deficit in dhotis and saris is, to a certain extent, offset by greater handloom production. Handloom production has gone up from 1798 million yards to 1863 million yards. Therefore, such a big rise in price is not justified by

[Shrimati Sucheta Kripalani]

the facts of the situation. Then, what is the reason for this big rise in price? This is accounted for by the peculiarity of the Indian market where marginal deficits are easily converted into large deficits and marginal surpluses lead to a glut. Being conversant with the Indian market and being conversant with the profiteering psychology of traders, the Government should have imported raw cotton at a much earlier stage which they failed to do. This would have prevented the rousing of profiteers' expectation on the knowledge of the shortfall of cotton production. Because of this failure, to import cotton in time we are now faced with the problem of high rise in price.

Government is now compelled to import raw cotton at a much higher price. Only today during Question Hour the Minister gave us information regarding cotton imports. We shall now also have to do our best to see that the mills produce three shifts. It is difficult to induce the mill-owners to start third shifts, obviously, because they know that when the slack season comes, they will have to face the lay-off problem. But recently so many factories have gone out of production. We have to meet the situation in some way. Therefore, the only answer at the moment seems to be to induce the mill-owners to start third shifts. We should also lay greater emphasis on cloth production in the Third Plan.

I am very sorry to say that the handloom industry, which is one of our oldest industries and which, to a certain extent, can help to ease the situation is now in great difficulty. The yarn price has gone up to such an extent that the handloom industry is facing very grave crisis.

In Kerala where they have got a sizable handloom industry, when I visited some of their units last month, it was brought home to me that they are very apprehensive that they will not be able to compete with the mills. The prices of yarn have gone to such an extent that this industry is facing a great crisis. Government should pay immediate attention to see that sufficient supply of yarn is made available to them.

I touch upon another commodity which is not as important as cloth or food; but, it is also an important commodity. I particularly make mention of it because the rise in price of that commodity in certain areas is totally unjustified—that is sugar. This rise in price, I feel, is due to controllable causes. If we can control effectively, we can bring down the prices.

I admit that sugar production this year is less. The supply of sugar in 1959, including the carry-over stock was 22·31 lakh tons as against an estimated requirement of over 22·66 lakh tons. Taking into consideration the pipeline of distribution which would hold up a certain percentage of stock, there is a little deficit which cannot be denied. But this deficiency does not justify the rise in price in some States. I would mention particularly West Bengal and U.P. where sugar is selling at Rs. 55 when the ex-factory price is Rs. 37·84. To my mind, therefore, the defect lies in the machinery of distribution.

In July 1959, Government started the nominee system. A list of nominees was to be submitted by the State Government to the Directorate here and under the rule one wagon of sugar was to be given to one nominee. In one State, I know this rule is observed more in the breach. Instead of one wagon, some nominees get 20, 30 or 40 wagons. These people are thus able to manipulate the market and hold up stocks. They are also buying up some of the small units, i.e., from those licencees who get one wagon. Then another defect is that licences are not given necessarily to those conversant with the sugar trade; but, it is given to coal dealers, iron dealers, salt merchants and others.

This is not a feature which cannot be controlled by Government. It is surely the duty of the Government to stop this racket and to see that their own rules are not broken with impunity but are observed.

In another State the problem has arisen because the stock are lying with the wholesalers either because nominees are not appointed or orders for releasing sugar stocks are not given in time. In getting these orders, they have to satisfy the officers at different stages. Because the officers are not satisfied, the stocks are lying and the price of sugar is rising and people are suffering.

I say these are cases which are remediable. Such things should be immediately checked and controlled. People should not be made to suffer for those commodities which are available in the country.

I feel that if we can, by price control, give relief to the masses in terms of the necessaries of life, not only will it help in our development programmes but it will detract greatly from the tensions in the political and social life. I feel that this is a matter where Government has given some attention, but that attention has neither been effective nor efficient. I would plead with the Government to pay more effective and more efficient attention in regard to the problem of supplying to the people the necessaries of life at proper prices.

I have finished, but before I sit down I just want to say one word about this problem which is agitating the minds of all the people, that is, the Chinese problem. I am in no position to conduct a post-mortem examination of the situation that has been created on our borders by the Chinese aggression. All that I want to say, and that too in all humility, is that we have to be extra careful in dealing with China. If I can use that vulgar phrase, we are dealing with very tough and very slippery customers and we have to be very careful in dealing with them.

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा कश्मीर) : चेअरमैन साहब, मैं आज के दिन सद्रे जम्हूरिया की उस तकरीर की ताईद करता हूं और खुश आमदीद कहता हूं जो उन्होंने इस ऐवान और दूसरे ऐवान के मेम्बरान के सामने की । इस बात में कोई शक नहीं है कोई दो रायें नहीं हो सकतीं इस में, कि उन की पिछली तकरीर से ले कर अब तक मुल्क में बहुत सी तरक्की हुई है और मुल्क एक बहुत बड़ी हद तक आगे चला गया है और तरक्की के जीने पर आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है । उन्होंने अपनी तकरीर में पिछले साल जो हम ने मन्सूबाबन्दी में तरक्की की है उस का भी जिक्र किया है, उन्होंने आने वाले साल में जो मजीद कदम उठा रहे हैं तरक्कियों की तरफ उस का भी जिक्र किया है । जहां तक हमारी मशीनी जिन्दगी, हमारी समाजी और इक्तसादी हालत का ताल्लुक है, वह हम सब के सामने है । हिन्दुस्तान ने मौजूदा हुकूमत के केयादत में बहुत तरक्की की है, और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि आइन्दा आने वाले सालों में भी हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी तरक्की करेगा । इस में कोई शक नहीं है ।

पिछले साल हमें चन्द अचानक होने वाली चीजों का सामना करना पड़ा । उन में एक चीज थी चीन का हमारी सरहदों में गैर दोस्ताना तौर पर घुस आना । यकीनन हिन्दुस्तान के तमाम लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस बात के हक में हैं कि इस इलाके से चीनियों को वापस जाना चाहिये । और हम बड़े अच्छे तरीके से, सिवा जंग के, जो कि मौजूदा दुनियां से हमारी रविश रही है, कि तमाम चीजों को, तमाम मसायल को, चाहे वह अन्दरूनी मसले हों या बेरूनी मुमालिकों के साथ मुतनाजा उमूर हम उन को दोस्ताना तरीके पर हल करेंगे । हम तमाम मसलों को बगैर किसी हथियार । के इस्तेमाल किये हुए खत्म करायेंगे । पिछले कई हजार सालों से हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी यही रविश रही है और यकीनन

[श्री अ० मु० तारिक]

हमें इस बात का फ़ख्र है और इस बात का पूरा भरोसा है कि हम इस में कामयाब हो जायेंगे ।

अभी चन्द दिनों की बात है, बल्कि कल ही इस ऐवान में हमारे वजीर आजम ने इस चीज को हमारे सामने रक्खा कि उन्होंने चीन के वजीर आजम को हिन्दुस्तान आने की दावत दी । यह एक बहुत बड़ा कदम है हिन्दुस्तानी शान और हिन्दुस्तानी रवायात के मुताबिक । हमारे वजीर आजम ने या हमारी हुकूमत ने यह कोई नई बात नहीं की है जिस के बारे में हमारे यहां के कुछ रहने वाले एहतजाज करें, कोशिश करें जवाहरलाल और उस की हुकूमत को कमजोर करने की । हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं, जो शायद इस ऐवान के हर मेम्बर के सामने होंगी । इसी दिल्ली में आज से चन्द साल पहले हिन्दुस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान के वजीर आजम का भी इस्तकबाल किया था । हमारी यह ख्वाहिश है, यह दयानत-दाराना कोशिश भी है, कि हमें पाकिस्तान के साथ सुलह करनी चाहिये । वह हमारा हमसाया मुल्क है । सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि और भी जितने हमसाये मुल्क हैं, चाहे दूर के हों या करीब के, चाहे हमारे मजाहिब के हों या न हों, हमें सब लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने चाहियें । यह हकीकत है जिस वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने, हिन्दुस्तान की हुकूमत ने, जिस वक्त हमारे वजीर आजम ने, पाकिस्तान के वजीर आजम का इस्तकबाल किया, उस वक्त हमारे सामने एक नक्शा था कि वह उस पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जो बात बात पर हर लहजों और हर लमहा हमें मुक्का दिखाता है—लियाकत अली खां की फिस्ट दुनियां की एक बात बन गई थी—पाकिस्तान वह पाकिस्तान है जिस ने कश्मीर पर हमला किया, आग लगाई, लोगों का कत्ले आम किया, हमारी मांओं और बहनों को उठाकर ले गये, लेकिन सिर्फ हिन्दुस्तानी रवायात की तहत, हिन्दुस्तानी शराफत की तहत, हम ने वहां के वजीर आजम का भी इस्तकबाल किया, उन पर मनों फूल न्योछावर किये । लेकिन अगर आज इस मुल्क के वजीर आजम ने चीन के वजीर आजम को भी दावत दी है इस मुल्क में आने की बगैर किसी शर्त के चीन के वजीर आजम ने भी हिन्दुस्तान के वजीर आजम का बगैर किसी शर्त के आने की दावत दी थी । यह ठीक है कि उन्होंने इस बात का तजकिरा नहीं किया था कि वह झगड़े के किन किन पहलुओं का जिक्र करेंगे । हम ने वजीर आजम चीन को आने की दावत दी । दुनियां का तरीका है कि अगर एक दुश्मन आप के घर पर आ कर दावत दे तो यकीनन उस दावत पर फिर से बुलावा दिया जाता है । यकीनन यह चाऊ एन-लाई से नहीं कहा है कि आप यहां तशरीफ लाइये और हम यह हिस्सा आप को बतौर जागीर के पेश करेंगे । इतना ही कहा है कि आप आइये, हम आप से बात चीत करना चाहते हैं । बात चीत के यह माने नहीं कि हम हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा किसी शख्स को, किसी भी अजीम ताकत को बतौर जागीर के देना चाहते हैं । लेकिन आज कल की दुनिया में हमने यह साबित कर दिया है कि नई दिल्ली मौजूदा सयासत का काबा हो सकता है । यहां ख्रुश्चेव भी आये हैं, आइजनहावर भी आये हैं, नासिर भी आ रहे हैं । लेकिन यह हमारी ही कोशिशों का नतीजा था कि आज कल दुनियां इस का फायदा उठा रही है । लेकिन इस का क्या किया जाय कि खुद हमारे कुछ दोस्त, खुद कुछ हमारे साथी इस तरकीब में लगे हुए हैं कि हमारी कोशिशें बेकार हो जायें । आज ही मेरी नजरों के सामने से एक पोस्टर गुजरा है । हमारी एक अंजूमन है उस की कोशिशें हैं कि चाऊ एन-लाई और जवाहरलाल की मुलाकात न होने पाये । अगर चाऊ एन-लाई से जवाहरलाल की मुलाकात नहीं होती है तो हिन्दुस्तान और चीन के ताल्लुकात यकीनन इतनी जल्दी तय

नहीं होंगे, जितनी जल्दी तय होने के हम ख्वाहा हैं। हिन्दुस्तान को यह देखना है कि क्या सिर्फ जंग से हम इस मामले को तय कर सकते हैं। यकीनन नहीं कर सकते। जंग से आज तक दुनियां का कोई मामला तय नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान की एक रवायत है, शायद बहुत से बुजुर्गों को भूल गई होगी। लेकिन मैं नौजवान हूं और बहुत कम पढ़ा लिखा हूं इस लिये जितना पढ़ा है वह मुझे याद है। जो बुजुर्ग बहुत पढ़े लिखे हैं उन को सब भूल जाता है। जब इस मुल्क के ऊपर सिकन्दर आजम ने हमला किया और पोरस मगलूब को लोग उस से सामने ले आये तो सिकन्दर ने उस से पूठा कि बतलाओ, मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं तो उन्होंने कहा कि वही सुलूक कीजिये जो एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिये। हम को भी बाहर के मुल्कों से, बावजूद उन की गल्तियों के, अच्छा वर्ताव करना चाहिये, उन को समझने की कोशिश करनी चाहिये और उन को समझाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): आप पहले शेख अब्दुल्ला को समझाइये।

श्री अ० मु० तारिक: माफ कीजिये, शेख अब्दुल्ला को हम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इस का क्या करें कि वह आप के रास्ते पर पढ़ गये, आप के चक्कर में आ गये और बुरी तरह उस चक्कर में फंस गये।

इस के अलावा मैं इस बात की तरफ भी आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ, जिस का तजकिरा सद्रे जम्हूरिया ने अपने ऐड्रेस में किया है, यकीनन हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहियें। लेकिन बेहतर ताल्लुकात कामन डिफेन्स कहने से नहीं हो सकते। कामन डिफेन्स कहना तो बड़ा आसान है। लेकिन आप ने क्या यह भी सोचा है कि जिस तरह के कामन डिफेन्स का तजकिरा आप फरमात हैं उस की तह में क्या है। एक तरफ तो यह है कि हिन्दुस्तान की एक-एक इंच जमीन के लिये हम लड़ना चाहते हैं, हम नारे बुलन्द करते हैं और लोगों को गलत रास्ते पर डालते हैं। कामन डिफेन्स की तहत आप हिन्दुस्तान के कुछ हिस्से को किसी की जागीर में देना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की मिल्कियत है हिन्दुस्तान किसी खास आदमी की मिल्कियत नहीं है। उस का कोई भी हिस्सा किसी शख्स को जागीर के तौर पर नहीं दिया जा सकता है। आज हमारे यहां इस लिये अफरा तफरी फैलाई जाती है कि यह कम्यूनिस्ट हैं, यह कांग्रेस वाले नहीं हैं। अरे साहब, हम कांग्रेसी अपने आप को बखूबी जानते हैं, आप को भी पहचानते हैं। आखिर हम सब आप के साथ खेले हुए हैं।

श्री वाजपेयी: आप कब से कांग्रेसी हो गये?

श्री अ० मु० तारिक: आप के इंटरप्शन से मैं परेशान तो हूंगा नहीं क्योंकि एक मजबूत जमात का नुमाइन्दा हूं।

एक माननीय सदस्य: खुद भी मजबूत हो भाई।

श्री अ० मु० तारिक: इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की मौजूदा जमाने में जो तरक्की है उस में तमाम जातियों को, तमाम लोगों को, इस मुल्क के तमाम रहने वालों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत के पनपने का मौका दिया जाय। हिन्दुस्तान में हम कम्यूनिटी डेवेलपमेंट की तहत बहुत कुछ कर सकते थे। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंट बेकार चीज है। यह दूसरी चीज है कि हमारी मजबूरियां, हमारी नाअहलियत, हमारी नासमझी किसी अच्छी चीज को बुरी चीज में भी तब्दील कर सकती है। जरूरत इस चीज की है कि हम अहलियत का इस्तेमाल

[श्री० अ० मु० तारिक]

करें, हम समझ बूझ को अमल में लायें । हम जाती चीजों को भूल जायें अगर यकीनन हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है । इस मुल्क में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से मजाहब के लोग हैं, बहुत सी जबानों के लोग हैं, बहुत सी रंगत के लोग हैं, लेकिन सब हिन्दुस्तानी हैं । हमारे सामने एक नजरिया होना चाहिये कि हम इस मुल्क के लोगों को, चाहे वह किसी मिल्लत से हों, किसी मजहब से हों किसी जात से हों, इकट्ठा ले चलें । अगर यहां के लोगों को हम एक साथ ले चलें तो हम हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे । कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के जरिये हम लोगों में बहुत अहसास पैदा कर सकते हैं । मुझे इस बात का भी शिकवा करना है .....

Mr. Chairman: The hon. Member may now conclude.

श्री अ० मु० तारिक : अभी तो मैं ने शुरू किया है ।

Mr. Chairman: He may take two minutes more.

Shri A. M. Tariq: Three minutes, Sir. Be generous to me.

मुझे इस बात का भी तजकरा करना कि हम अपने इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के तहत, इन्फार्मेशन के जरिये लोगों को मौजूदा तरक्की के बारे में बहुत कुछ बतला सकते हैं ।

जब इंग्लैंड में लेबर गवर्नमेंट पावर में आई तो उस ने नेशनलाइजेशन का काम शुरू किया और काम शुरू करने के साथ-साथ उस ने वहां के लोगों को चूंकि इतनी समझ थी उन में इसलिये टेलिविजन के जरिये, अखबारों के जरिये , रेडियो के जरिये और दुसरी चीजों के जरिये आवाम में उसके बारे में प्रचार किया लोगों को उस के बारे में जानकारी दी ताकि लोगों को मालूम हो जाये कि नेशनेलाइजेशन का मकसद क्या है और लोगों को इस गलतफहमी में न डाला जाय कि उस के माने कुछ गोलमोल हैं । लेकिन मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में हमारा मुल्क पीछे रहा है और अब तक बहुत से लोगों को जिनमें किसी हद तक मैं भी शामिल हूं, यह समझ में नहीं आया कि नेशनेलाइजेशन के क्या मानी हैं । यह कौमी या स्टेट की मिलिक्यत है या किसी एक खास फर्म या शख्स की ? इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि यहां के लोगों को यह साफ तौर से समझाया जाये कि नेशनेलाइजेशन के क्या मानी हैं ?

आज करप्शन का भी जिक्र चला हुआ है । हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत सी बातें चलती हैं और हमारे नेता की जबान में उन में बहुत सी अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं । बहरहाल सब बातें साथ-साथ चलती हैं। लेकिन हम किसी भी सूरत में इस चीज को फरामोश नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में करप्शन आया है, मुल्क में करप्शन को लाया गया है, मुल्क में करप्शन को फैलाया जा रहा है और यकीनी तौर पर उस का तदारूक होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य: करप्शन के लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री अ० मु० तारिक : हम और आप दोनों ।

एक माननीय सदस्य : आप ज्यादा हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : खैर शुक्र है आप अपनी जिम्मेदारी कबूल तो करते हैं भले ही वह आप के मुताबिक चाहे कम हो । बहरहाल,

हमें इस चीज की तरफ तवज्जह देनी चाहिये और हमें अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इस काबिल बनाना चाहिये ताकि वह आम लोगों का ऐतमाद हासिल कर सकें और लोग यह समझने लगें कि वाकई हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वह मुल्क के लिये कर रहे हैं ।

करप्शन के बारे में मुझे यह कहना है कि इसी ईवान में जब एक दफा इस का जिक्र चला था तो उस जमाने के फाइनेन्स मिनिस्टर देशमुख साहब ने कहा था कि करप्शन नहीं है और उस पर हमारे हाउस के एक मुअज्जिज मेम्बर नें, जो कि आज इस ऐवान में मौजूद हैं, मेरा इशारा श्री महावीर त्यागी की तरफ है और त्यागी जी ने उस वक्त कहा था कि करप्शन है तो देशमुख साहब ने फरमाया था कि खाली इस तरह से कहने से कि करप्शन है, किसी के खिलाफ मुकदमा तो चल नहीं सकता है । आप कौनक्रीट कैसेज लाइये, इल्जामात लाइये, लोगों के नाम दीजिये तभी उस पर कुछ सोच विचार हो सकता है । वाकई अगर मुल्क में कुछ लोगों के पास ऐसा मवाद है और ऐसे वाकयात हैं जिस से हम किसी शख्स को चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो या छोटा क्यों न हो, यह साबित कर सकें कि वह वाकई करप्ट है तो यकीनन मौजूदा हकूमत उस का खैरमकदम करेगी लेकिन हवाई बातें बनाना, हवाई किले बनाना ही उन की मंशा है, तो फिर उस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता है ।

हमें यकीन है कि मौजूदा हुकूमत इन तमाम बातों की तरफ तवज्जह देगी और मुल्क में ऐसे हालात पैदा करेगी कि जिससे कि यहां के लोगों में फिर से ऐतमाद पैदा हो जाय । इन चन्द अल्फाज के साथ मैं सदर जम्हूरियत की तकरीर का शुक्रिया अदा करता हूं ।

شبی اے - ایم - طارق (جموں اور کشمیر) : چیرمین صاحب - میں آج کے دن صدر جمہوریہ کی اس تقریر کی تعید کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں جو انہوں نے اس ایوان اور دوسرے ایوان کے سمبران کے سامنے کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے - کوئی دو رائیں نہیں ہو سکتیں اس میں - کہ ان کی پچھلی تقریر سے لے کر اب تک ملک میں بہت سی ترقی ہوئی ہے اور ملک ایک بہت بڑی حد تک آگے چلا گیا ہے - اور ترقی کے زینے پر آہستہ آہستہ جا رہا ہے - انہوں نے اپنی تقریر میں پچھلے سال جو ہم نے منصوبہ بندی میں ترقی کی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے - جہاں تک ہماری مشیلی زندگی ہماری سماجی اور اقتصادی حالت کا تعلق ہے - وہ ہم سب کے سامنے ہے - ہندوستان نے موجودہ حکومت کے قیادت میں بہت ترقی کی ہے - اور ہمیں اس بات کا پورا بھروسہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہندوستان ایک بہت بڑی ترقی کرے گا - اس میں کوئی شک نہیں ہے -

پچھلے سال ہمیں چلد اچانک ہونے والی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا - ان

میں ہمارے بہار کے کچھ رہنے والے احتجاج کریں - کوشش کریں جواہرلال اور اس کی حکومت کو کمزور کرنے کی - ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں - جو شائد اس ایوان کے ہر ممبر کے سامنے ہوں گی - اسی دہلی میں آج سے چند سال پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی استقبال کیا تھا - ہماری یہ خواہش ہے - یہ دیانتدانہ کوشش ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ صلح کرنی چاہیئے - وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے - صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اور بھی جتنے ہمسایہ ملک ہیں - چاہے دور کے ہوں یا قریب کے - چاہے ہمارے مذاہب کے ہوں یا نہ ہوں - ہمیں سب لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے چاہئیں - یہ حقیقت ہے کہ جس وقت ہندوستان کے لوگوں نے ، ہندوستان کی حکومت نے ، جس وقت ہمارے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کا استقبال کیا ، اس وقت ہمارے سامنے ایک نقشہ تھا کہ وہ اس پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ، جو بات بات پر ہر لہجہ اور ہر لمحہ ہمیں مکہ دکھاتا ہے — لیاقت علی کی فسٹ دنیا کی ایک بات بن گئی تھی — پاکستان وہ پاکستان ہے جس نے کشمیر پر حملہ کیا ، آگ لگائی ، لوگوں کا قتل عام کیا ،

[شری اے - ایم - طارق]

میں ایک چیز تھی چین کا ہماری سرحدوں میں غیر دوستانہ طور پر گھس آنا - یقیناً ہندوستان کے تمام لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت اس بات کے حق میں ہیں کہ اس علاقہ سے چینیوں کو واپس جانا چاہیئے - اور ہم بڑے اچھے طریقہ سے سوا جنگ کے - جو کہ موجودہ دنیا میں ہماری روش رہی ہے - کہ تمام چیزوں کو - چاہے وہ اندرونی مسئلے ہوں یا بیرونی ممالک کے ساتھ متنازعہ امور ہم ان کو دوستانہ طریقہ پر حل کریں گے - ہم تمام مسئلوں کو بغیر کسی ہتھیار کے استعمال کئے ہوئے ختم کرائیں گے - پچھلے کئی ہزار سالوں سے ہندوستان کے اندر ہماری یہی روش رہی ہے اور یقیناً ہمیں اس بات کا فخر ہے اور اس بات کا پورا بھروسہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے -

ابھی چند دنوں کی بات ہے - بلکہ کل ہی اس ایوان میں ہمارے وزیر اعظم نے اس چیز کو ہمارے سامنے رکھا کہ انہوں نے چین کے وزیر اعظم کو ہندوستان آنے کی دعوت دی - یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ہندوستانی شان اور ہندوستانی روایات کے مطابق - ہمارے وزیر اعظم نے یا ہماری حکومت نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی ہے جس کے بارے

ناصر بھی آ رہے ہیں - لیکن ہماری ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آج کل دنیا اس کا فائدہ اُٹھا رہی ہے - لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ خود ہمارے کچھ دوست - خود کچھ ہمارے ساتھی اس ترکیب میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کوششوں بیکار ہو جائیں - آج ہی میری نظروں کے سامنے سے ایک پوسٹر گزرا ہے - ہمارے ایک انجمن ہے اس کی کوشش ہے کہ چاو این لائی اور جواہر لال کی ملاقات نہ ہونے پائے - اگر چاو این لائی سے جواہر لال کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تو ہندوستان اور چین کے تعلقات یقیناً اتنی جلدی طے نہیں ہوں گے - جتنی جلدی طے ہونے کے ہم خواہاں ہیں - ہندوستان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف جانگ سے ہم اس معاملے کو طے کر سکتے ہیں - یقیناً نہیں کر سکیں گے - جانگ سے آج تک دنیا کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا ہے - ہندوستان کی ایک روایت ہے - شائد بہت سے بزرگوں کو بھول گئے ہوگی - لیکن میں نوجوان ہوں اور بہت کم پڑھا لکھا ہوں اس لئے جتنا پڑھا ہے وہ مجھے یاد ہے - جو بزرگ بہت پڑھے لکھے ہیں ان کو سب بھول جاتا ہے - جب اس ملک کے اوپر سکندراعظم نے حملہ کیا اور پورس مغلوب کو لوگ اس کے سامنے لے آئے تو سکندر نے ان سے پوچھا کہ بتلاو - میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے کہا کہ وہی ہماری ماؤں اور بہنوں کو اٹھا لے گئے - لیکن صرف ہندوستانی روایات کے تحت ، ہندوستانی شرافت کے تحت ہم نے وہاں کے وزیر اعظم کا بھی استقبال کیا ، ان پر ملوں پھول نچھاور کئے - لیکن اگر آج اس ملک کے وزیر اعظم نے چین کے وزیر اعظم کو بھی دعوت دی ہے - اس ملک میں آنے کی بغیر کسی شرط کے چین کے وزیر اعظم نے بھی ہندوستان کے وزیر اعظم کو بغیر کسی شرط کے آنے کی دعوت دی تھی - یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ جھگڑے کے کن کن پہلوؤں کا ذکر کریں گے - ہم نے وزیر اعظم چین کو آنے کی دعوت دی - دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر ایک دشمن آپ کے گھر پر آکر دعوت دے تو یقیناً اس دعوت پر پھر سے بلاوہ دیا جاتا ہے - یقیناً یہ چاو این لائی سے نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے اور ہم وہ حصہ آپ کو بطور جاگیر کے پیش کریں گے - اتنا ہی کہا ہے کہ آپ آئیے - ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں - بات چیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان کا کوئی حصہ کسی شخص کو ، کسی بھی عظیم طاقت کو بطور جاگیر کے دینا چاہتے ہیں - لیکن آج کل کی دنیا میں ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نئی دہلی موجودہ سیاست کا کلیہ ہو سکتا ہے - یہاں کرشچیو بھی آئے ہیں - آئزنہاور بھی آئے ہیں -

[شری اے - ایم - طارق]

سلوک کیجئے جو ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہئے - ہم کو بھی باہر کے ملکوں سے - باوجود ان کی غلطیوں کے - اچھا برتاو کرنا چاہئے- ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہئے -

شری واجپئی (بلرامپور) - آپ پہلے شیخ عبداللہ کو سمجھئیے -

شری اے - ایم - طارق - معاف کیجئے - شیخ عبداللہ کو ہم نے بہت سنبھالنے کی کوشش کی - لیکن اس کا کیا کریں کہ وہ آپ کے راستہ پر پڑ گئے - آپ کے چکر میں آگئے اور بری طرح اس چکر میں پھنس گئے -

اس کے علاوہ میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جس کا تذکرہ صدر جمہوریہ نے اپنے ایڈرس میں کیا ہے - یقیناً ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہئے - لیکن بہتر تعلقات کامن ڈیفینس کہنے سے نہیں ہو سکتے - کامن ڈیفینس کہنا تو بڑا آسان ہے - لیکن کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس طرح سے کامن ڈیفینس کا تذکرہ آپ فرماتے ہیں اس کی تہ میں کیا ہے - ایک طرف تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک ایک انچ زمین کے لئے ہم لڑنا چاہتے ہیں - ہم نعرے بلند کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط راستہ پر ڈالتے ہیں - کامن ڈیفینس کی تحت آپ ہندوستان کے کچھ حصہ کو کسی کو جاگیر میں دینا چاہتے ہیں - ہندوستان کی ملکیت ہے ہندوستان - ہندوستان کسی خاص آدمی کی ملکیت نہیں ہے - اس کا کوئی بھی حصہ کسی شخص کو جاگیر کے طور پر نہیں دیا جا سکتا ہے - آج ہمارے یہاں اس لئے افواہ تفری پھیلائی جاتی ہے کہ صاحب یہ کمیونسٹ ہیں - یہ کانگریس والے نہیں ہیں - ارے صاحب - ہم کانگریسی اپنے کو یوہی سمجھتے ہیں - آپ کو بھی پہچانتے ہیں - آخر ہم آپ کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں -

شری واجپئی- آپ کب سے کانگریسی ہوگئے -

شری اے- ایم طارق - آپ کے انٹرپیشن سے میں پریشان تو ہوں گا نہیں کیونکہ ایک مضبوط جماعت کا نمائندہ ہوں -

ایک مانئیہ سدسیہ - خود بھی مضبوط ہو جائی -

شری اے- ایم- طارق - اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی موجودہ زمانہ میں جو ترقی ہے اس میں تمام جاتیوں کو - تمام لوگوں کو - اس ملک کے تمام رہنے والوں کو بلا لحاظ مذہب

و ملت کے پلپنے کا موقع دیا جائے
هندوستان میں هم کمیونٹی ڈیولپمنٹ
کے تحت بہت کچھ کر سکتے تھے
میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا
که کمیونٹی ڈیولپمنٹ بیکار چیز هے -
یه دوسری چیز هے که هماری
مجبوریاں - هماری نااهلیت - هماری
نا سمجھی کسی اچھی چیز کو بری
چیز میں بھی تبدیل کر سکتے هیں
ضرورت اس چیز کی هے که هم
اهلیت کا استعمال کریں - هم سمجھ
بوجھ کر عمل میں لائیں - هم ذاتی
چیزوں کو بھول جائیں اگر یقیناً
همیں اس ملک کو آگے لے جانا هے
اس ملک میں بہت سے لوگ
هیں - بہت سے مذاهب کے لوگ
هیں - بہت سی زبانوں کے لوگ
هیں - بہت سی رنگت کے لوگ رهتے
هیں - لیکن سب هندوستانی هیں
همارے سامنے ایک نظریه هونا چاهئے
که هم اس ملک کے لوگوں کو -
چاهے وه کسی ملت سے هوں -
کسی مذهب سے هوں - کسی ذات
سے هوں - اکٹھا لے چلیں - اگر یہاں
کے لوگوں کو هم ایک ساتھ لے
چلیں تو هم هندوستان کی بہت
بڑی خدمت کر رهیں گے - کمیونٹی
ڈیولپمنٹ کے ذریعه هم لوگوں میں
احساس پیدا کر سکتے هیں - مجھے
اس بات کا بھی شکوا کر .

Mr. Chairman: The hon. Member may now conclude.

شری - اے - ایم - طارق - ابھی تو
میں نے شروع کیا هے -

Mr. Chairman: He may take two minutes more.

Shri A. M. Tariq: Three minues, Sir. Be generous to me.

مجھے اس بات کا بھی تذکرہ کرنا هے که
هم اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی تحت
انفارمیشن کے ذریعه لوگوں کو موجوده
ترقی کے بارے میں بہت کچھ بتلا
سکتے هیں -

جب انگلینڈ میں لیبر گورنمنٹ
پاور میں آئی تو اس نے نیشنلائزیشن کا
کام شروع کیا اور کام شروع کرنے کے ساتھ
اس نے وهاں کے لوگوں کو چونکه اتنی
سمجھ تھی ان میں اس لئے ٹیلیویزن
کے ذریعه - اخباروں کے ذریعه - ریڈیو
کے ذریعه اور دوسری چیزوں کے ذریعه
عوام میں اس نے بارے میں پرچار
کیا لوگوں کو اس کے بارے میں
جانکاری دی تاکه لوگوں کو اس
غلط فہمی میں نه ڈالا جائے که اس
کے معنی کچھ گول مول هیں -
لیکن مجھے یه افسوس کے ساتھ
کہنا پڑتا هے که اس معاملے میں
همارا ملک پیچھے رها هے اور اب
تک بہت سے لوگوں کو جن میں
کسی حد تک میں شامل
هوں یه سمجھ میں نہیں آیا که
نیشنلائزیشن کے کیا معنی هیں - یه
قومی یا اسٹیٹ کی ملکیت هے یا

[شری اے - ایم - طارق]

کسی ایک خاص قوم یا شخص کی - اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ صاف طور سے سمجھایا جائے کہ نیشنلائزیشن کے کیا معنی ہیں - آج کرپشن کا بھی ذکر چلا ہوا ہے - ہمارا ملک بہت بڑا ہے بہت سی باتیں چلتی ہیں اور ہمارے نیتا کی زبان میں ان میں بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں - بہر حال سب باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن ہم کسی بھی صورت میں اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں کرپشن آیا ہے - ملک میں کرپشن کو لایا گیا ہے - ملک میں کرپشن کو پھیلایا جا رہا ہے اور یقینی طور پر اس کا تدارک ہونا چاہئیے

ایک مان نیہ سدسیہ - کرپشن کے لئے ذمہ دار کون ہے -

شری اے - ایم - طارق - ہم اور آپ دونوں -

ایک مان نیہ سدسیہ - آپ زیادہ ہیں -

شری اے - ایم - طارق - خیر شکر ہے آپ اپنی ذمہ داری قبول تو کرتے ہیں بھلے ہی وہ آپ کے مطابق چاہے کم ہو - بہر حال ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہئیے اور ہمیں اپنے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو اس قابل بنانا چاہئیے تاکہ وہ عام لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں اور لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ واقعی ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں - کرپشن کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اسی ایوان میں جب ایک دفعہ اس کا ذکر چلا تھا تو اس زمانے کے فائنانس منسٹر دیش مکھ صاحب نے کہا تھا کہ کرپشن نہیں ہے اور اس پر ہمارے ہاؤس کے ایک معزز ممبر نے جو کہ آج اس ایوان میں موجود ہیں میرا اشارہ شری مہاویر تیاگی کی طرف ہے اور تیاگی جی نے اس وقت کہا تھا کہ کرپشن ہے تو دیش مکھ صاحب نے فرمایا تھا کہ خالی ویگلی اس طرح کہنے سے کہ کرپشن ہے کسی کے خلاف مقدمہ تو چل نہیں سکتا ہے - آپ کونکریٹ کیسز لائیے - الزامات لائیے لوگوں کے نام دیجئیے تبھی اس پر کچھ سوچ وچار ہو سکتا ہے - واقعی اگر ملک میں کچھ لوگوں کے پاس ایسا مواد ہے اور ایسے واقعات ہیں جس سے ہم کسی شخص کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یا چھوٹا کیوں نہ ہو - یہ ثابت کر سکیں کہ وہ واقعی کرپٹ ہے - تو یقیناً موجودہ حکومت اسکا خیر مقدم کریگی لیکن ہوائی باتیں بنانا ، ہوائی قلعے بنانا ہی ان کی منشا ہے تو پھر اس بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے -

ہمیں یقین ہے کہ موجودہ حکومت
ان تمام باتوں کی طرف توجہ دیگی
اور ملک میں ایسے حالات پیدا کریگی
کہ جس سے یہاں کے لوگوں میں پھر
سے اعتماد پیدا ہو جائے - ان چند
الفاظ کے ساتھ میں صدر جمہوریہ کی
تقریر کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

Shri Bhanja Deo (Keonjhar): Mr. Chairman, Sir, I thank the President for the excellent Address which he has made to us, particularly for the firm foreign policy regarding China which he has asked his Government to follow. It was very forcefully put before the House yesterday by my hon. friend Shri Masani and today by Acharyaji as to what should be our policy with China. I do not want to deal at length on this particular issue because many hon. Members have already spoken about it forcefully and elaborately.

I will now digress to the Third Five Year Plan about which the President has given an indication as to what should be our targets and what should be our achievements. In this regard, Sir, I will try to deal first with the shortfall which our Second Five Year Plan has gone through and which should make us wiser while formulating the next Plan, which according to the President should be such as would generate results in an economy which should be conducive to the growth of our country.

In this connection, it is expected to be published for public comments shortly. The official thinking on the Plan as available from various official and non-official sources suggests an outlay of the order of about Rs. 9,900 crores to about Rs. 10,000 crores. This outline as suggested by the Planning Commission was also discussed by the All-Parties Committee of the Members of Parliament which met on 22nd December, 1959.

First of all, I would like to emphasise here the acute shortage of power that our country is going through at present. This is probably not confined to any particular State, though one of the States from where I come due to acute shortage of this power cannot go ahead with a ferro-alloy plant and a ferro-chrome plant which the private sector has been very keen to put up in that State.

Then I will come to coal. The target for coal in this current Five Year Plan was put at 60 million tons. The indications are based on the output during the preceding year, that the output might be about 47 million tons during the year 1959, at the most 50 tons by the end of the current Plan period. Probably this is due to the fact that too much emphasis was given on the public sector which the public sector could not fulfil because they had to raise coal from new fields which were virgin and they did not have the proper technical assistance and know-how to assist them in this matter. That is why I say they should be particularly wise while formulating the target of, I understand, 110 million tons for the next Plan period.

Another disturbing factor is that our export of coal has fallen down considerably and we are gradually losing the markets to which our coal used to go before. Apart from the loss of foreign exchange which will do harm to our industries from the long-term point of view, because once the foreign market is lost it may be extremely difficult to win it back for Indian coal, this development brings into focus the situation of shortage created by the Government's attitude to rely on the production of collieries in the public sector only.

Now I come to industrial machinery. The objective is that by the end of the Fourth Five Year Plan the requirements of the main categories of the

[Shri Bhanja Deo]

plant and equipments under mining, power and transport should be produced within the country. It was very gratifying to note that today while presenting the Railway Budget, the hon. Railway Minister has assured us that as far as transport facilities in the railways are concerned, the production of plants necessary for the Third Five Year Plan will be undertaken in the country.

But, Sir, together with the heavy industries, I would like to draw your attention to the small-scale industries for which we have recently invited a team of Japanese experts. They have given their opinion as to what our line should be to encourage these industries. With your permission, Sir, I would like to quote a few of their remarks. The delegation, it is stated, has made a number of recommendations, the most important of which relate to the organisation of credit for small-scale industries. It is suggested that in the recommendations while the Government's policy has been to make available financial assistance, the agencies which have been entrusted with this task still follow cautious and conservative policy, which in short does not fulfil the aims and objects of the Government. They have, therefore, suggested certain measures to overcome this handicap including the adoption of a credit guarantee system whereby a credit guarantee fund under the State financial corporations would be established for guaranteeing the applications of small-scale units. They have also suggested the creation of a credit insurance system whereby a Credit Insurance Fund mainly contributed by the Central Government would be established in the Reserve Bank of India. Under this proposal, the sole insurer of the credit insurance scheme would pay to credit guarantee fund, and the scheme would be applicable only when the credit guarantee fund, after repaying the money on behalf of the borrower, can collect it from him. Establishment of a State co-operative bank or banks and the utilisation of the branch offices of the State Bank of India as agencies of the State Financial Corporation has been recommended.

While the Japanese experts have nothing but praise for industrial estates, they have suggested the setting up of small industries corporation at all State levels to provide machinery and equipment on easy instalments to the small and medium sized units. Improvements and promotion of the ancillary industries, unified control over supply of raw materials, spares and accessories of national standard are the other points in their proposals.

15 hrs.

It is understood and generally appreciated that in order to maintain the present rate of investment, the country will have to go for planning on a bigger scale than previously till a stage is reached when the economy can be described to be self-generating, the basic essential of the Plan should also take into consideration the capacity and the resources available. Self-sufficiency in food is essential and saving of foreign exchange which is at present incurred in importing foodgrains will be a single big item which can contribute effectively to releasing foreign exchange for other essential projects. This will require greater attention to agricultural production, price stabilization and improvement of warehousing capacity. A reordering of the priorities in the Community Development programme will also be necessary to channelise expenditure borne in productive channels and less in social services. Because from our experience in the development projects, we find that to give our agricultural sector a very high priority, we will have to spend a considerable amount of our foreign exchange to import foodgrains which in a self-generating economy, it will not be compatible and will not be possible for our country to continue to do so.

The estimates of Rs. 10,000 crores has been based on the price level of 1952-53 and since then the prices have

gone up with no prospect of their coming down. It would be legitimate to assume that the financial target of Rs. 10,000 crores will mean a plan less than or equal to the second Five Year Plan in terms of physical targets.

The second important fact which has got to be faced is the gap in the resources and the estimated outlay, and it has been estimated that foreign aid to the extent of Rs. 2,000 crores will have to be secured for successful implementation of the third Plan. The Government of India have signed a credit arrangement with the Soviet Union which may make available Rs. 180 crores for various projects in the third Five Year Plan, prominent among them being the expansion in the capacity of Bhilai,....

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Bhanja Deo: At least five more minutes may be given to me.

Mr. Chairman: Two minutes.

Shri Bhanja Deo: It would, therefore, mean that foreign aid on a much larger scale than ever before from western powers will have to be enlisted for the success of the third Plan. India, will, therefore, have to rely mainly on the World Bank and the D.L.F. loans for this purpose. D.L.F. loans will make credit available only on the condition that 80 to 90 per cent. of the purchases are made in U.S.A. Since the prices of machinery and capital equipment in the U.S.A. are stated to be 25 to 30 per cent. higher than those of similar plant and machinery elsewhere, it will add to the cost of the Plan and reduce it in terms of physical targets.

Now, I shall come to another factor which is very important and which is connected with the Plan. It is about the price structure. A firm policy towards price stabilisation is essential. This brings into scope a discussion on the adverse effects of deficit financing especially in the second Five Year Plan on the economy of the country. Formerly, it was stated that the deficit financing would be limited to Rs. 900 crores but now it looks that the deficit financing in the second Plan will be of the order of 1,200 crores. This has set in motion inflationary tendencies with the whole-sale and the consumer price index going up. The Finance Minister feels that high prices are the result of shortage but the figures will show that it is a factor not so much of shortage but of the money in circulation chasing goods which are not adequate.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Bhanja Deo: I shall finish now. This, therefore, calls for a target for price level and the cost of living during the third Plan period.

The President has mentioned that during the third Five Year Plan, our national income will be doubled. But I am sorry that I cannot be happy with it, because doubling of national income does not necessarily mean doubling of the *per capita* income. If it had meant doubling of the *per capita* income, it would have surely benefited the country, and I would have congratulated the Government on that score. But only saying that the national income will be doubled does not mean anything, because the national income of the country consists of income from different groups like the rural population and the population in the cities. The *per capita* income in the cities will vary when compared to that of the rural population. I would again draw the attention of the Government to the very high prices, the soaring prices, that prevail in the country and it will be gratifying if particular attention is paid to that aspect.

Shri T. Subramanyam (Bellary): Mr. Chairman, Sir, the President's Address is a restrained and a dignified statement of the main events and achievements of last year and a call to the nation to bear its burdens and responsibilities. It is, at the same time, an appeal to the people to show co-operation and understanding for the implementation of the socio-economic

[Shri T. Subramanyam]

plans in the defence of the country and ultimately to achieve success in the cause of world peace. There is no note of despondency or defeatism in the Address. Nor is there a note of overstatement or complacency.

15.08 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Criticism has been made, firstly, about the description by the President as breach of faith in regard to the incursions by the Chinese into our territory, and it is said to be improper and objection is sought to be taken to it. Our Government and our leaders have made it abundantly clear that the borders between China and India have been long established by usage, tradition, custom and by international agreements. In the face of this clear-cut attitude of the Government, why should there be any objection? It is also regretted that the Chinese incursions are a definite and distinct violation of the principles involved in *Panchsheel*. Non-aggression and promotion of conditions for achieving peaceful co-existence are a vital part of *Panchsheel* and the Chinese, by their incursion, by committing a glaring aggression, have violated the principles. Therefore, the description of the President is absolutely warranted and justified and my hon. friends on the other side need not have taken any objection to this.

Another hon. friend has said that this has come as a god-send. It is rather unfortunate and uncharitable, because we have laid very great stress on achieving friendly relations with China and on establishing cordial relations. Any diversion of our resources, either in man power or material, to strengthen our defences on the border would mean a great stress and strain on our implementation of the Plan. Therefore, it is not at all a god-send. On the other hand, it is an event which has come as a saddening and a most disquietening thing to the Government and the people of India.

Our Prime Minister has written a letter to the Chinese Premier asking him to come here. I shall very briefly deal with this. I do not think there is anything wonderful in this. To those of us who have been accustomed to Gandhian way of life and technique, this should be very natural. Gandhiji extended his invitation to his worst opponents. My hon. friend said yesterday that if the Chinese Premier comes here, we will be in a war of nerves. The first principle of the Gandhian way was to practise absolute fearlessness, while at the same time trying to be friendly to one's opponents....

Shri M. R. Masani (Ranchi—East): That caused the experience of the Rajkot fast.

Shri T. Subramanyam: But it was not a negation of Gandhiji's principles of being fearless and friendly to our opponents. Gandhiji wrote a letter to Lord Wellingdon after his return from the Round Table Conference. The nervousness was on the other side. So, our leader, Shri Nehru, drew his inspiration from Gandhiji and was trying to reinforce that way of life in his own experience. So, I do not think we should have any apprehension or nervousness if Mr. Chou En-lai comes here. Let the Prime Ministers discuss and come to an agreement. (*Interruption*).

The President's Address deals with industrial and agricultural production. We celebrated the tenth anniversary of our Republic recently. During the last 10 years, from an agricultural economy, we are trying to forge ahead into an industrial economy and we are well on the way to it. What Europe took nearly 150 to 200 years during its history of industrial revolution, we have tried to compress in the last decade, full of events of utmost importance and significance.

In the agricultural sector, there has been fairly good improvement, but not much. The President himself strikes a note of caution and says that our

annual import of foodgrains to the tune of crores of rupees is distressing and a strain on our foreign exchange; also our per-acre yield of crops is the lowest in the world. So, there is no question of any complacency at all in this matter. It is a frank appraisal of the actual situation. The crux in the agricultural sector is to use improved processes, better seeds, better implements, better manure, etc. The World Agriculture Fair is being held and farmers from various States have visited it. It is a very good thing and I am sure both the departmental officers and private farmers will be benefited by it. I met some young farmers when they were about to take leave of us. They informed me that there is a lack of agricultural implements like plough-shares, bund-farmers, buck-scrapers, bullock-cart tyres, etc. Some of these were being sold in the black market. It is really an unfortunate thing that even some of the multi-purpose co-operative societies at the taluk level have not been able to supply these iron and steel implements. It has been stated that the position has now improved.

I do not want to go into the past. It is futile. Let us take care of the present and the future. Our three steel plants have gone into production. We have doubled our production of pig iron. Production of steel also has substantially increased. So, first priority must now be given to the manufacture of agricultural implements. We should see that the various small-scale industries at the district level produce these implements. It is not necessary to have large-scale factories for this purpose. I have seen some industries at the district level and they are very good. This will partly solve the unemployment problem and the transport difficulties also will be overcome. Centralism also will be avoided.

In the matter of distribution of iron and steel, I feel there is excess of centralism. The Iron and Steel Controller at Calcutta has got the power to distribute licences to various multi-purpose co-operative societies at taluk level. They have to struggle hard; they are told that in the present position of inadequacy of iron and steel, they cannot get those licences. I am sure Government will do something about it. There should be greater co-ordination between the Ministries of Industry and Steel, Mines and Fuel and the Agriculture Ministry, so that these rudimentary and primary requirements of the agriculturists may be fully met.

We are talking of integrating the results of research in the various agricultural research institutions, so that modern practices may be fully utilised by the farmer for more production. I must frankly confess that the agriculture department is not attracting first rate men. There are some brilliant people in some research stations, but by and large, first rate men are not attracted to it. Recently one brilliant boy came to me for advice after passing the intermediate examination. I asked him to join some agricultural college. But he said "there are no promotions and prospects in that line and so I shall go for some other technical course". That sort of feeling is there in the country. We should try to overcome it as far as possible and see that a healthy feeling prevails, so that brilliant young men may be attracted to the agriculture department.

In para 19, the President himself has said:

> "Measures are being taken to step up progressively the output in these cadres and to provide increasingly better career opportunities and a higher status for the old and new entrants."

I am sure that this will be implemented as early as possible.

Let me make a brief reference to industrial production. The index rose from 138 to 149. The steel plants have gone into production. Machine tools have gone into production to a larger extent and we are achieving very good progress. Our object, of course,

[Shri T. Subramanyam]

is to achieve a self-sustaining and self-generating economy. We can achieve that only when we are able to finance our own projects, iron and steel plants, big machine-building plants, etc. with our own resources and at the same time produce technicians. and technologists who will draw up designs, manufacture equipment instal the factories and see that they start working. If all that is done by our own people with our own resources, we can say that we have achieved a self-sustaining and self-generating economy. It is our object to see that this position is achieved by the third Five Year Plan. As the President has stated, before this, our administrative system should be geared in such a way that delays are avoided. At present the rules of procedure and departmentalism are such that instead of expediting matters, they operated as obstacles. This should be avoided. I do not say that a particular individual is responsible for this. We have got very good officers in various departments. Some of the new IAS men are very good and they take a constructive, earnest and sincere attitude in implementing our plans. Still, so far as the procedures and the rules of departmentalism are concerned, we should try to radically modify them in such a way that they do not become hurdles or obstacles but they enable us to see that the work is expedited and completed as early as possible.

Then, we must achieve a balanced regional development of all parts of the country. There is a feeling in the South—I must give expression to it—that as much attention as ought to be given has not been given. For instance, steel factories are sought to be started. Let them be started. We require as much steel as possible; it may be ten million tons or even more. In South India there are places where pilot plants could be started. For instance, in my own district of Bellary we have got iron ore of the most precious variety. I am not saying this because it is in my district. Russian scientists and technologists have stated that the iron ore of Bellary district is of the most precious variety in the world, and it is available in abundant quantities. It is not an exaggeration. We can utilize that. With regard to the cost of the actual product, we can take into consideration various factors like freight, distance to be covered and the transport facilities.

Coming to transport, in the Third Five Year Plan we are going to be short of railway capacity, and the other modes of transport will not be able to cope up with the increasing demands from our economy. Therefore, we must try to decentralise, whether it is steel, or fertilizer, or other products. I am mentioning steel only as an example. We must try to decentralise the industries so that the problem of transport could be overcome, freight could be minimized and people could get these things as early as possible.

Oil is playing a very important part in our economy. We had been hoping that oil research will forge ahead and make progress. We hope that the Ministry of Oil, Mines and Fuel will get more support from Government and they will expedite the drilling and other processes to make our country self-sufficient, or at least meet a substantial proportion of our requirements.

I was saying that we must forge ahead with regard to the integration of the various modes of transport—rail, road and waterways. There should be more of extension of railways in South India. We want railway lines should be extended from Kottur to Harihar, from Rayadurg to Chitaldurg in Mysore and other places in South India. All these years it could not be done because of the non-availability of iron girders, rails and such things. Now that three steel factories are going to produce steel, this sort of excuse should not come in, and they must see that South India also has more railway lines under the Third Plan.

Water transport has been neglected all these years, and I am sure Government will pay greater attention to it. We must try to link up all the various river systems in India, as it is very necessary for a developing economy like ours. The CWPC are now seized of the matter and they have been trying to have a plan for this purpose. I am sure that Government will try to get it as early as possible.

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने श्री चाऊ एन-लाई को जो पत्र भेजा है और जिस में उन्हें दिल्ली आने की दावत दी गई है, उस से एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। यह पत्र ५ तारीख को भेज गया और उस के बाद ८ तारीख को संसद की बैठक आरम्भ हुई। ईमानदारी का तकाजा था कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ ऐसे संकेत दिये जाते जिन से यह पता लगता कि सरकार ने चीन के सम्बन्ध में अपनी नीति को बदलने का फैसला कर लिया है।

राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के अधिष्ठाता है। वर्ष में एक बार वह संसद के सामने भाषण देते हैं। उन के भाषण से कम से कम शासन की नीति में परिवर्तन का संकेत मिलना चाहिये था। किन्तु राष्ट्रपति जी से कहलवाया गया कि चीन ने हमारी सामान्य सीमा पर एकतरफा कार्य किया है। उन्हों ने यह भी कहा कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और यह भी कि मेरी सरकार उचित शर्तों के साथ और उचित अवसर पर शान्तिपूर्ण बातचीत और दृढ़ता से देश की प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है। जब राष्ट्रपति जी संसद् के सदस्यों के सामने यह भाषण कर रहे थे उस से पहले हमारे प्रधान मंत्री ने चीनी प्रधान मंत्री को दिल्ली आने का निमंत्रण दे दिया था। मुझे भय है कि राष्ट्रपति जी को गलत स्थिति में डाल दिया गया है। हमारे प्रधान मंत्री ने संसद के प्रति ईमानदारी से काम नहीं लिया है। श्री चाऊ एन-लाई को उन का निमंत्रण

सरकार की अब तक की उदघोषित तथा संसद द्वारा पुष्ट नीतियों के सर्वथा प्रतिकूल है। बम के धड़ाके की तरह से यह नीति का परिवर्तन सर्वथा अप्रत्याशित, अनावश्यक और असम्मानजनक है।

कल जब यहां स्थगन प्रस्ताव रखा गया तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारी हर दम यह नीति रही है कि हम रास्ता निकालने के लिये हर किसी से मिलने के लिये तैयार रहते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने पिछले चालीस साल का भी हवाला दिया। मैं इतने पुराने अरसे में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ उन से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने श्री चाऊ एन-लाई को रंगून आने का निमंत्रण क्यों ठुकराया था। उन्हों ने उस समय यह कहा था :

"How can we reach agreement on principles when there is such complete disagreement about facts."

उन्हों ने यह भी कहा था अपने १६ नवम्बर के पत्र में :

"While I am ready to meet at a suitable time and place, I feel that we should concentrate our immediate efforts on reaching interim understanding which will help in easing the present tension and will prevent the situation getting worse. Thereafter, the necessary preliminary steps might be taken and the time and place of meeting could be fixed."

उन्हों ने यह भी लिखा था :

"It is necessary that some preliminary steps are taken and the foundations of our discussion laid."

मैं पूछना चाहता हूं कि २६ दिसम्बर और ५ फरवरी के बीच में कौन से प्रमुख कदम उठाये गये हैं कौन सा अन्तरिम

[श्री वाजपेयी]

समझौता किया गया है, क्या बातचीत के लिये कोई आधार निश्चित किया गया है ? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री अगर रंगून जाते और चीन के प्रधान मंत्री अगर दिल्ली आते हैं तो इस में कोई फर्क पड़ता है । एक राष्ट्र के नाते हम प्रतिष्ठा की इतनी छोटी बातों को ले कर नहीं चल सकते । सवाल यह है कि अगर उस समय यह शर्त लगायी गयी थी कि प्रेलिमिनरी स्टेप लिये जाने चाहियें, अन्तरिम एग्रीमेंट होना चाहिये, तब बात होगी, और अगर उस समय यह शर्त ठीक थी और इसलिये प्रधान मंत्री रंगून नहीं गये, तो आज भी वह शर्त ठीक है । और अगर प्रधान मंत्री जी समझते हैं कि हमारी यह शर्त गलत थी तो वह साफ शब्दों में यह बात कहें । वह नीति बदल सकते हैं, उन के साथ सदन का बहुमत है, देश की जनता भी उन से प्यार करती है । अगर उन को परिवर्तन करना था तो वह सदन को और देश की जनता को अंधेरे में न रखते । राष्ट्रपति जी के भाषण से इस बात के संकेत मिलने चाहियें थे कि सरकार की नीति में परिवर्तन हो रहा है । लेकिन मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि इस प्रकार के परिवर्तन का कोई संकेत नहीं दिया गया । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इस बीच में क्या उन्हें कोई संकेत मिले हैं, क्या श्री पारथा-सारथी पीकिंग से कोई संदेश ले कर आये हैं, क्या सोवियत नेताओं ने उन्हें कोई आश्वासन दिया है, वह कौन सा दबाव है, वह किस का प्रभाव है जिस में आ कर प्रधान मंत्री ने श्री चाऊ एन-लाई को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है । मुझे लगता है कि सारे तथ्य हमारे सामने नहीं रखे गये और हो सकता है उसी कारण हम चाऊ एन-लाई को दिल्ली बुलाने के निमंत्रण का विरोध करते हैं, प्रधान मंत्री जी को इस सदन को विश्वास में लेना चाहिये । जो ५ फरवरी को उन्हों ने पत्र लिखा है उस में भी उन्हों ने कहा है :

"I do not see any common ground between our respective viewpoints."

उन्हों ने यह भी कहा है :

"Although any negotiations on the basis you have suggested are not possible, still I think it might be helpful for us to meet."

पहले उन्हों ने कहा था कि जब तक इन्टेरिम एग्रीमेंट नहीं होगा, मिलना यूजफुलन हीं रहेगा । अब वह कहते हैं कि मिलना हैल्पफुल हो सकता है । किस आधार पर कहते हैं ? हमें बताया जाये समझाया जाये । हम समझने के लिये तैयार हैं । लेकिन मालूम होता है कि कोई आधार नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने समाचारपत्रों के संवाददाताओं से कहा कि हम ने इस लिये बुलाने का निमंत्रण दिया है क्योंकि दुनिया हमें कह रही थी कि तुम मिलने तक के लिये तैयार नहीं, वर्ल्ड ओपोनियन हमारे खिलाफ हो रही थी । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री दुनिया की राय की चिन्ता करती है, मगर इस निमंत्रण का देश की चालीस करोड़ जनता पर क्या मनोवैज्ञानिक असर होगा, इस की चिन्ता नहीं की गई । दुनिया की चिन्ता करने से पहले देश का विचार करना चाहिये और मुझे दुख है कि यह निमंत्रण जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं है । मेरा निवेदन है कि सरकार की चीन सम्बन्धी नीति धीरे धीरे बदलती जा रही है और हमारे प्रधान मंत्री जी अपने ऊंचे आसन से फिसलते जा रहे हैं । इस सदन के सामने उन के दो रूप आये हैं । एक दिन सदन में खड़े हो कर उन्हों ने नेशन इन आर्म्ज की चर्चा की थी । राज्य सभा में उन्हों ने चर्चिल के ब्लड, टायल एंड टीयर्ज के शब्दों को दोहराया था । दो स्वरूप हैं । एक स्वरूप ऐसे राष्ट्र नायक का है, जो स्वाभिमान से भर कर आत्म-सम्मान के साथ आक्रमण का मुकाबला करना चाहता है और एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति का चित्र है, जो देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहा है । एक चित्र

के ऊपर ब्रिटेन को विजय दिलाने वाले चर्चिल की छाया है तो दूसरे चित्र के ऊपर संतुष्टीकरण की नीति अपना कर हिटलर का हौसला बढ़ाने वाले चैम्बरलेन की छाया है। मैं जब ये शब्द कहता हूं तो मुझे बड़ा दुःख होता है, लेकिन ये दोनों चित्र हमारे सामने आये हैं। ऐसा लगता है कि एक विभक्त व्यक्तित्व—एक डिवाइडिड पर्सनेलिटी हमारे सामने है।

जब प्रधान मंत्री ने नेशन इन आर्म्ज की चर्चा की थी तो मैं ने उन्हें बधाई दी थी। मैंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि देश का सम्मान आप के हाथों में सुरक्षित है। मगर उन के नये पत्र से यह विश्वास हिल गया है और मैं चाहता हूं कि वह इस विश्वास को फिर से प्रतिष्ठापित करें। इसके लिए उनको यह स्पष्टीकरण करना चाहिये कि आखिर वह श्री चाऊ-एन लाई से किस आधार पर बात करने जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि मिलने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किस आधार पर मिलना होगा? अब कहा जाता है कि हम मिल सकते हैं और बात भी करेंगे, मगर समझौते की बात नहीं करेंगे। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि बात कहां खत्म होगी और समझौते की बात कहां शुरू होगी। अगर श्री चाऊ-एन-लाई नई दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली के मौसम पर चर्चा करने नहीं आ रहे हैं। धान पैदा करने की चीनी पद्धति क्या है इसको समझाने के लिए भी वह नहीं आ रहे हैं। इसके लिये तो एशीकल्चर फेयर में चाइनीज पैविलियन काफ़ी है। इसके लिए श्री चाऊ-एन-लाई को पेकिंग से नई दिल्ली आने का कष्ट देने की आवश्यकता क्या है? हमें अपने को धोखे में नहीं रखना चाहिए। स्पष्ट है कि चीन से सीमा सम्बन्धी विवाद के बारे में बात होगी। किस आधार पर बात होगी? मैं प्रधान मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह इस मसले पर कहां तक जाने के लिए तयार हैं। मेरे हृदय में आशंका है कि शायद हम अक्साई-चिन के इलाके को चीन को सौंप कर शान्ति को खरीदना चाहते हैं।

श्री च० द० पाण्डे (नैनीताल) : बिल्कुल नहीं।

श्री वाजपेयी : अगर यह बात नहीं है तो मैं चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री जी एक बार फिर से, उनके पत्र के कारण संसद के सदस्यों और देश की जनता के मन में जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, सन्देह पैदा हो गए हैं, उन का निराकरण करें।

होना तो यह चाहिए था कि हमारे प्रधान मन्त्री और सरकार शीत ऋतु का लाभ उठा कर चीनी आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से खदेड़ने की कोशिश करते, लेकिन यहां तो समर्पण की सामग्री संजोई जा रही है। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हम भारत की भूमि पर विदेशी सेना को बर्दाश्त न करेंगे। मैं उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं लेकिन काश्मीर की ४२ हजार वर्ग मील भूमि पाकिस्तान के कब्जे में है। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मगर गुलाम काश्मीर में जिस देश की सेना है, वह भारत नहीं है। काश्मीर में विदेशी सेना मौजूद है और लद्दाख और लौंगजू में भी विदेशी सेना मौजूद है। अगर देश में पाकिस्तान के साथ सैनिक गठबन्धन करने की बातें होती हैं—मैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर होती हैं—तो उसके मूल में यह भावना है कि भारत सरकार की सुरक्षा नीति और विदेश नीति अपने राष्ट्र के हितों का संवर्द्धन करने में असफल साबित हो गई है। जब हमें अपनी कमजोरी का अहसास होता है, तो हम इधर उधर आंखें फैलाते हैं। दूसरों के साथ गठबन्धन करने की बातें बन्द हो जायेंगी, अगर सरकार शक्ति के साथ, साहस के साथ, जो भारत की भूमि विदेशियों के कब्जे में है, उसे मुक्त करने के लिये कदम उठायेगी। लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि देश के सामने जो परिस्थितियां हैं उसका दृढ़तापूर्वक सामना करने का सामर्थ्य

[श्री वाजपेयी]

और साहस सरकार के भीतर नहीं है । अगर प्रधान मन्त्री चीनी सेना को लद्दाख और लांगजू के क्षेत्र से निकाल कर बाहर नहीं कर सकते, तो कम से कम वह उनके साथ कोई ऐसा समझौता तो मत करें, जो राष्ट्र के लिए अपमानजनक हो और जिससे राष्ट्र की जनता का मनोबल टूट जाये ।

प्रधान मन्त्री जी ने श्री चाऊ एन-लाई को लिखा है कि अगर वह आयेंगे तो उनका सरकारी स्वागत होगा । सरकार स्वागत कर सकती है और अगर आवश्यकता हो तो फ़ौज के जवान हवाई अड्डे पर इकट्ठे किए जा सकते हैं, दिल्ली के स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर खड़ा किया जा सकता है मगर यह जनता का स्वागत नहीं होगा । जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है—छोटी सी पार्टी है—हम श्री चाऊ एन-लाई को नई दिल्ली बुलाने का विरोध करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस विरोध को प्रकट भी करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : ब्लैक फ्लैग्ज़ ?

श्री वाजपेयी : इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कह दूं । हमारे यहां बहुत से विदेशी महमान आते हैं । उनके स्वागत का हमने एक तरीका बना रखा है । समय आ गया है कि उस तरीके में परिवर्तन किया जाये । किसी के स्वागत के लिए कितनी भीड़ आती है ? मानो यह मापदण्ड हो गया है इस बात का कि हम तटस्थता की नीति पर कितना चलते हैं और चलना चाहते है कि नहीं । मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं और देश की बहुसंख्यक जनता यह चाहती है कि हम किसी गुट के साथ शामिल न हों, मगर जो विदेशी महमान आते है उनके स्वागत का हमने ऐसा तरीका अपना रखा है कि लोगों की जो भीड़ जमा होती है, उसको देख कर विदेशी समाचारपत्र और सम्वाददाता और उस देश के रहने वाले इस बात का अनुमान लगाते हैं कि भारत किधर झुक रहा है, मानो हम कोई टाइट रोप डांसिंग कर रहे हैं । और अगर छुट्टी का दिन नहीं है, भीड़ अगर नहीं आई, भले ही हम दफ़्तर की छुट्टी कर दें और स्कूलों के लड़कों को भी लाने की कोशिश करें, अगर फिर भी लोग नहीं आए, तो यह समझा जाता है कि हम किसी गुट की तरफ़ झुक रहे हैं । मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब विदेशी महमानों के स्वागत की पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए । कितने लोग आते हैं, यह हमारी विदेश नीति की तटस्थता का मापदण्ड नहीं हो सकता । होना भी नहीं चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस पद्धति को बदलने के बारे में विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय इस विवाद में भ्रष्टाचार की भी चर्चा हुई है । मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही अगर हम बिगड़ जायें, तो इससे कोई परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है । अगर हम बिगड़ते हैं,तो लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार ज़रूर है, जिससे हमें गुस्सा आता है । शेष कोपेन पूरेत । संस्कृत की एक कहावत है कि जब तर्क काम नहीं देता, तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है ।

पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : और ज़ोर ज़ोर से बोलता है ।

श्री वाजपेयी : यह क्रोध, यह गुस्सा तर्क का स्थान नहीं ले सकता है । भ्रष्टाचार की अगर चर्चा है, तो समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार ज़रूर है । यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र वन्हिः अगर धुंआ है, तो आग होनी चाहिए । प्रश्न यह है कि हम भ्रष्टाचार के सवाल को यहां पर कानून के चश्मे से न देखें। हो सकता ह कि बहुत सी चीज़ें कानून की पकड़ में न आयें, मगर उचित अनुचित और भले बुरे के अन्तर्गत आ जायें । अब कहा जाता है कि हर एक का प्रमाण लाइये । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न तो श्री सी० डी० देशमुख से किया जाना चाहिए, जिन्होंने कतिपय आरोप लगाये हैं और मैं

प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सी० डी० देशमुख के साथ उनका जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसको वह प्रकाशित कर दें, उसे सदन की मेज़ पर रख दें। मैं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने के पक्ष में हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि वह आयोग इलैक्शन कमीशन जैसा नहीं होना चाहिए। उस आयोग के साथ उस की प्रासीक्यूटिंग मशीनरी भी अलग होनी चाहिए। अगर इलैक्शन कमीशन जैसा वह आयोग हुआ और नीचे मामलों की जांच पड़ताल करने और प्रमाण इकट्ठा करने, गवाह जुटाने के लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं हुई तो वही बात होगी जो राजस्थान में नाथद्वारा काण्ड में हुई थी केवल ऊपर आयोग नियुक्त कर देने से काम नहीं चलेगा। राज्यों और केन्द्र के प्रशासन की मशीनरी से अलग उस आयोग की एक प्रासीक्यूटिंग मशीनरी भी होनी चाहिये जो उन आरोपों की जांच करे, तथ्य इकट्ठा करे, तथा प्रमाण लाए। मैं समझता हूं कि ऐसे एक आयोग को नियुक्त करने की आज आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। केन्द्रीय सरकार ने बम्बई प्रान्त के विभाजन का जो निर्णय किया है, सब ने उसका स्वागत किया है। अच्छा होता अगर यह निर्णय पहले लिया जाता और जो कटुता उत्पन्न हो गई है वह होने न पाती। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। हम ठीक राह पर आ गए हैं। लेकिन हमारा निवेदन है कि जिस ढंग से यह काम किया जा रहा है उससे मालूम पड़ता है कि बम्बई को बांटने का मामला केवल कांग्रेस पार्टी का घरेलू मसला है और इसको इस ढंग से हल किया जा रहा है कि जो और भी लोग हैं उनके मन में भी कुछ नए प्रश्न, कुछ नई शंकायें खड़ी हो रही हैं। अभी बम्बई और मैसूर का सीमा सम्बन्धी विवाद ठीक तरह से हल नहीं हुआ। गुजरात को सहायता मिलना आवश्यक है मगर वह किस रूप में दी जाए, इसका विचार होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की यह भावना हो कि गुजरात को सहायता देने के लिए उससे चौथ वसूल की जा रही है जिसे मराठी में खंडनी कहते हैं, कि गुजरात का अलग प्रान्त बन रहा है इसलिए महाराष्ट्र को चौथ देनी होगी तो यह ठीक नहीं है। जो कुछ सहायता देनी है वह केन्द्रीय सरकार को देनी चाहिए और महाराष्ट्र की जनता को और विरोधी दलों को भी विश्वास में लेकर बम्बई को बांटने के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए।

लेकिन बम्बई के साथ-साथ अब पंजाब के बटवारे की भी आवाज उठाई जा रही है। कल दिल्ली के एक सदस्य बोले थे जिन्होंने महा दिल्ली की बात कही और साथ ही साथ यह भी कहा कि दिल्ली में कोई रिसपांसिबिल गवर्नमेंट नहीं है। मैं तो उन्हें जिम्मेदार आदमी समझता था लेकिन उन्होंने बात तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की कही। अगर देश में सभी विधान सभायें भंग कर दी जायें और केवल संसद् ही उनका शासन चलाये और देश में यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट हो जाय तो भी मैं समझता हूं कि लोकतंत्र रहेगा। यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह विधान सभायें होनी चाहियें। और दिल्ली में तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो अपना विचार करते हैं, जो जनता की भलाई और देश के कल्याण की चिन्ता नहीं करते, वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बांट दो, भले ही उत्तर प्रदेश बंटने के लिए तैयार न हो, हरियाना को भी अलग कर दो और महा दिल्ली बना दो और बाद में उस के सिंहासन पर हम को प्रतिष्ठित कर दो। मैं समझता हूं कि महा दिल्ली के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाना की जो समस्या है, हरियाना की जो उपेक्षा की जा रही है, उस पर विचार होना चाहिये पंजाब को बांटने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा बनाने की आवश्यकता है हिमाचल

[श्री वाजपेयी]

को पंजाब में मिलाया जा सकता है । जो भाषा की समस्या है उस का हल पंजाब के बटवारे से नहीं निकलेगा । छोटे-छोटे राज्य हमारे देश की आर्थिक प्रगति में सहायक नहीं हो सकते । जैसे-जैसे हम विकास करते जा रहे हैं और जैसे-जैसे देश में औद्योगीकरण हो रहा है, ये जो राज्यों की सीमायें हैं, ये अपना महत्व खोती जा रही हैं । और प्लानिंग तो एक ऐसा केन्द्रीय विषय है जिस मे अधिकाधिक अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में जा रहे हैं । आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी भाषा भाषी वर्ग को इस बात का अनुभव नहीं होना चाहिये कि उस की भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस की भाषा को मिटाने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसी भावना पंजाब में है तो मैं समझता हूं कि गलत है । पंजाबी भी हमारी भाषा है, पंजाबी भी हमें पढ़नी चाहिये, पंजाबी हम बोलते हैं, पंजाबी को सीखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और पंजाबी के साथ-साथ पंजाब में हिन्दी का भी बराबर का स्थान होना चाहिये । मैं नहीं समझता कि भाषा के विवाद को राजनीतिक क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है और इसलिए महादिल्ली के निर्माण का सवाल ही पैदा नहीं होता । राजनीतिक क्षेत्र में जो असन्तुष्ट नेता हैं, वे महादिल्ली का नारा लगा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उस नारे का कोई महत्व नहीं होगा । पंजाब की परिस्थिति और बम्बई की परिस्थिति अलग है । पंजाब की परिस्थिति मे बम्बई की परिस्थिति को लागू करना ठीक नहीं होगा । पंजाब की अलग समस्या है । उस के निराकरण के लिए प्रयत्न होना चाहिये, लेकिन बम्बई के साथ जोड़ कर उस को देखने की आवश्यकता नहीं है । जब हमारे सामने विदेशी आक्रमण का संकट है, जब हमें निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करना है तब हम छोटे-छोटे राज्यों की मांग ले कर खड़े नहीं हो सकते और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मांगों के प्रति सरकार ठीक प्रकार का रवैया अपनायेगी ।

श्री खादीवाला (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का भाषण हमारे पिछले एक साल के कार्यों का लेखा जोखा है । अपने भाषण के प्रारम्भ में ही उन्हों ने चीन की चर्चा की है और चीन की कार्रवाई को उन्हों ने विश्वासघात की संज्ञा दी है । चीन के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो बातचीत करने के लिए अपनी रज़ामन्दी प्रकट की है, वह हमारी तरफ़ से प्रारम्भ नहीं हुई, पहले चीन ने ही मुलाकात के लिए उन को लिखा था और उस ने रंगून में इस बातचीत को करने का सुझाव दिया था । वह बात खत्म हुई और बहुत दिन तक इस पर चर्चा होती रही । उस के बाद जो कुछ भी वातावरण बना उस को देखते हुए ही हमारे लीडर जो हैं, हमारे जो प्रधान मंत्री हैं, उन्हों ने मुलाकात के लिए चीन के प्रधान मंत्री को हिन्दुस्तान आने का निमंत्रण दिया है । इस से अधिक इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

हमारे राष्ट्रपति जी ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया है । पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में काफी काम हुए हैं । इन दस बारह बरसों में कोई भी गांव या कसबा ऐसा नहीं बचा है जहां कुछ न कुछ काम न हुआ हो, चाहे वहां सड़क बनी हो, स्कूल खुले हों, अस्पताल खुले हों, कुएं बने हों, तालाब बने हों, बांध बने हों या कुछ और बना हो, कुछ न कुछ जरूर वहां बना है । मैं समझता हूं कि इन दस बारह बरसों में काफी फर्क पड़ गया है, देश में काफी जागृति पैदा हुई है, और हम यह कह सकते हैं कि पिछले बारह बरसों में उत्पादन भी दुगना हो गया है । आज से दस पंद्रह बरस पहले जो चीजें विदेशों से आती थीं वे सब

की सब या तो आज हिन्दुस्तान में बनने लग गई हैं या उन के बनाने का आज यहां प्रयत्न हो रहा है ।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अनाज का भी जिक्र किया है और कहा है कि अनाज के आयात पर आज भी हमारे देश का काफी पैसा बाहर जाता है । वैसे तो अनाज में भी हम ने देखा कि पिछले वर्षों में उस का उत्पादन काफी बढ़ा है । उस उत्पादन को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि उस के इतने बढ़ने के बाद कमी क्यों है ? मैं तो यही कहूंगा कि आज से पहले हम यह देखें कि हमारे देश में अनाज की खपत कितनी थी । अनाज की खपत हमें मालूम है । हम यह जानते हैं कि पहले करोड़ों आदमियों को एक वक्त पेट भर खाना नहीं मिलता था और बहुत कम लोग अच्छी तरह खा पी सकते थे । यहां करोड़ों आदमी ऐसे थे जो ज्वार की रोटी, चटनी और कांटा से अपना पेट भरते थे और बहुत मुश्किल से अपना पालन पोषण करते थे । लेकिन आज हम देखते हैं कि अनाज की जरूरत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ी है, और उसके साथ हमारी पापुलेशन भी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि जिस की वजह से हमारे देश में अनाज की काफी कमी है । मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस में काफी अनाज पैदा होता है—यानी मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश में जोन बनने के सम्बन्ध में पिछले समय हमारे पाटिल साहब ने कहा था कि मध्य प्रदेश और बम्बई का जोन बनाया जाये । और बम्बई और मध्य प्रदेश का जोन इसलिये बनाया जाये कि अब सारा देश एक है । उस में कोई फर्क नहीं होना चाहिये । उन की यह बात ठीक है । मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन जब एक बार पहले जोन बना था तो उस के बनने से वहां की हालत यह हो गई थी कि तमाम अनाज जहां वह महंगा बिकता था वहां चला जाता था । उस के बाद जो अनाज पहले १४, १५ या १६ रु० मन बिकता था वह ३४, ३५ रु० मन बिकने लगा । समानता का मतलब यह है कि हर प्रदेश में समानता हो । आज बम्बई को हम लें । जोन बनने के बाद वह के आदमियों, किसानों की आमदनी, वांके मजदूरों की आमदनी, वहां के एम्प्लायीज की आमदनी को लें और मध्य प्रदेश के लोगों की आमदनी को लें तो दुगना और तिगुना फर्क मालूम होगा । अभी हमारे प्राशि के एम्प्लायीज की हड़ताल हुई थी देखोंकि उन की पे बहुत कम रक्खी गई है । इस लिये हड़ताल हुई थी कि चीजों के भाव ज्यादा महँगे होते जाते हैं । यह भी एक कारण है जिस की वजह से आज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को कह रही है कि जोन एक नहीं बनाया जाना चाहिये, हां, अगर ज्यादा अनाज हो तो जरूर उसे बाहर भेजना चाहिये । होता यह है कि पोर्ट पर अनाज विदेशों से आता है । यहां का अनाज दूसरी जगह को जाता है और वहां का अनाज जो उतरता है वह आकर यहां बिकता है । उस पर काफी खर्च होता है । अनाज के सम्बन्ध में मैं यह बतालाऊं कि आज भी हमारी सरकार द्वारा काफी प्रयत्न किया जा रहा है कि उस का उत्पादन काफी हो ।

मध्य प्रदेश तीन प्रदेशों और एक कमिश्नरी को मिला कर बनाया गया है । अभी राष्ट्रपति जी ने बम्बई के दो विभाग करने की बात कही है । हमारे मध्य प्रदेश के बनने के बारे में जब आयोग की रिपोर्ट निकली तो स्वयम् प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि यह प्रदेश बड़ा बेडौल बनाया गया है । आप तीन वर्षों के आंकड़ों को देखिये । अभी तक तीनों प्रदेशों में अलग अलग कायदे कानून चलते हैं । इन प्रदेशों के ४९८ कानून कायदे अभी तक उस में चलते हैं । उन का एकीकरण नहीं हुआ । जमीन का एकीकरण नहीं हुआ, वहां की शिक्षा का एकीकरण नहीं हुआ, वहां की पे का एकीकरणनहीं

[श्री खादीवाला]

हुआ । हर एक बात में काफी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं । आयोग ने लिखा था कि यह प्रदेश जो होगा उस में आने जाने के साधन--रोड्स और रेलवेज--ज्यादा से ज्यादा बनाये जायेंगे । उस में खनिज पदार्थ काफी हैं। यह सब बातें उस वक्त लोगों को बताई गई थीं और यही समझ कर हम लोगों ने यह बात मानी थी कि यह जो प्रदेश बन रहा है उस में जिन साधनों की कमी हो वे पूरे किये जायें । लेकिन आज हम क्या देखते हैं । मैं अनुभव से कह सकता हूं कि छोटे प्रदेश ज्यादा अच्छी तरह चल सकते हैं । छोटे प्रदेशों में अगर कहीं भी कोई कठिनाई हो, तकलीफ हो तो वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं होती । आज हम देखते हैं कि बावजूद इस के कि हमारे यहां की हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है कि हम अपने प्रदेश को अच्छा कर सकें, परन्तु आज भी हमारे प्रदेश में क्षेत्रीय भावना मौजूद है । वहां महाकौशल के, विंध्य प्रदेश के, मध्य भारत के और भोपाल राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी हैं, वहां के कार्यकर्ता हैं, उन में भी अपनी-अपनी तरफ खींचने की भावना आज भी मौजूद है । अगर एक कर्मचारी है और एक सेक्रेटरी है जो कि दोनों एक क्षेत्र के हैं, तो सेक्रेटरी यह देखेगा कि उस कर्मचारी की तरक्की कैसे हो और दूसरे जिस आदमी को तरक्की का हक है उस की तरक्की का हक किसी तरह से पीछे ढकेल कर अपने आदमी को उस की जगह पर पहुंचा दिया जाये । पिछले समय में कर्मचारियों की इतनी बड़ी हड़ताल होने का कारण सिर्फ यही नहीं था । हमारा जो एकीकरण हुआ उस में एकता की जो भावना पैदा होनी चाहिये थी नीचे से ऊपर तक, वह नहीं हो पाई । इस की वजह से उस समय असन्तोष पैदा हुआ । इस लिये मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि या तो यह एकीकरण ठीक से हो और जिस तरह से अन्य प्रदेशों को लाभ पहुंच रहा है वैसा ही इस प्रदेश को भी पहुंचे और उन की आमदनी के साधन काफी हों, नहीं तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से बम्बई के सम्बन्ध में दुबारा विचार हो रहा है उसी तरह से मध्य प्रदेश के लिये भी विचार किया जाय । जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा "हमारा प्रदेश काफी बेडौल है ।" आज हम बम्बई और कलकत्ता बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं लेकिन अगर हमें अपने प्रदेश में झबुआ से बस्तर को जाना हो तो काफी समय लगता है । तीन चार रोज लगते हैं क्योंकि वहां पर आने जाने के साधन काफी नहीं हैं । काफी बड़ा प्रदेश है । उस की सरहद उड़ीसा की सरहद से मिलती है, बम्बई की सरहद, उत्तर प्रदेश की सरहद और मद्रास की सरहद से मिलती है ।

एक माननीय सदस्य आखिर आप चाहते क्या हैं ?

श्री खादीवाला : राष्ट्रपति जी ने बम्बई के लिये दो प्रदेशों की बात कही है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बात के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिये, नहीं तो आगे जा कर हमारे प्रदेश का सवाल भी सामने आ सकता है । हम नहीं चाहते कि बम्बई की जो हालत हो गई, वहां प्रदेशों को बनाने के लिये जो कुछ हुआ वह हमारे यहां हो । हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन यह भावना जरूर है हर एक के दिमाग में, हर एक के मन में, जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) आप की राय क्या है इस को तो स्पष्ट कीजिये । आप के प्रदेश का भी पुनः विभाजन हो ?

श्री खादीवाला : मैं ने जो कुछ कहा है उसी से समझ लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी जानते हैं, वह जो कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री खादीवाला : आज भी कहीं कहीं शक्कर पर राशनिंग की बात कही जाती है। शक्कर के बारे में आज हम देखते हैं कि आज वह १ रु० ४ आ० और १ रु० ६ आ० सेर के भाव से बिकती है। उस की खास कठिनाई हमारे यहां है जिसका भी एक कारण है। हम ने यह देखा है कि आज भी मिलों के भीतर शक्कर की हजारों बोरियां पड़ी हुई हैं, और जिस तरह से हम पहले उसका वितरण करते थे उस तरह से अब नहीं कर रहे हैं। हम ने कुछ कोटा बांध दिया है और उस कोटे के बंधने की वजह से आज देश में शक्कर की कमी है। यही वजह है कि जब भी यहां कोई बात उठती है तो हम कहने लगते हैं कि शक्कर की कमी है।

जब शक्कर की कमी हम बतलाते हैं तो सारे देश में उसका असर होता है और जो ब्लैक मार्केट करने वाले लोग होते हैं वह उस शक्कर को दबाते हैं और उसके बाद में उसका भाव बढ़ता है। जहां तक चीनी के उत्पादन का सवाल है वह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है। सन् ४१, ४२ में चीनी का भाव रुपये में पांच सेर था। १ रुपये में ५ सेर चीनी मिलती थी और यह तब था जब कि आज से आधी चीनी भी इस देश में पैदा नहीं होती थी लेकिन उस वक्त उसकी खपत अधिक नहीं थी। उस वक्त उसको कोई नहीं लेता था, कोई नहीं खाता था, उसकी बिक्री कम होती थी और उसका कारण यह है कि पहले हमारे लोगों का जीवन स्तर इतना ऊंचा उठा हुआ नहीं था जितना कि आज वह उठा हुआ है। आज हालत यह है कि हर किसान और मजदूर के घर में चीनी का इस्तेमाल होता है और चीनी और चाय का उनके बीच में इतना प्रचार हो गया है कि जिस किसान के घर में मैं पहुंच जाऊंगा तो वह कहेगा कि अरे दादा खादीवाला चाय तो पिये जाओ। वैसे देखा जाय तो आज चीनी की कमी नहीं है लेकिन आज पहले की अपेक्षा हमारा स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो गया है और चीनी, कपड़े और करीब-करीब हर चीज के बारे में हमारा स्तर ऊंचा हो गया है और आज हर एक को वह चीजें चाहिएं और इसलिए उनकी मांग काफी है। आज चीनी की कमी नहीं है लेकिन उसकी व्यवस्था की तरफ अगर ध्यान दिया जाय तो ठीक होगा।

16 hrs.

पशुधन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब १६ करोड़ रुपये की खली हमारे यहां की विदेशों में जाती है, चापड़ा भेजा जाता है। मकई जो होती है उसका स्टार्च बनाते हैं। अगर हमें अपने पशु-धन की उन्नति करनी है और जैसा कि हम प्रदर्शिनी आदि में दर्शाते हैं तो इसके लिये मेरा यह कहना है कि यह जो खली और घास इत्यादि पशुओं के लिये खिलाने की चीजें हैं और जिन से दूध का उत्पादन होता है यह देश के बाहर नहीं भेजी जानी चाहिए।

एक बात मैं और आप की सेवा में कहना चाहता हूं और उसके लिए हर दफे मैं कहता हूं कि हमारे यहां पर इस लोक-सभा में कई ऐसे हमारे भाई हैं, प्रतिनिधि हैं, मेम्बर हैं, जिनको कि यह देखकर दुःख होता है कि यहां पर हिन्दी में इतना कम काम होता है कि मैं ने पहले भी कहा कि क्वैश्चन (प्रश्न) जो भेजे जाते हैं वह अंग्रेजी में तो सारे क्वैश्चन आते हैं लेकिन उनका हिन्दी में तर्जुमा नहीं होता है। यहां भी जब हिन्दी में अगर कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका हिन्दी में जबाब होता है तो कहते हैं कि उस की अंग्रेजी करो लेकिन अगर हिन्दी वाले यह कहना शुरू कर देंगे कि आप इसकी हिन्दी करो तो आप कहेंगे कि यह अच्छी बात नहीं है। हालांकि इसका उनको हक है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कार्यवाही अंग्रेजी समझने वालों की भी और हिन्दी समझने वालों की भी समझ में आ जाये। मैं यह नहीं चाहता कि यहां पर

[श्री खादीवाला]

खाली हिन्दी में कार्यवाही हो और जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनकी वह समझ में न आय लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि हिन्दी वाले और अंग्रेजी वाले कम से कम बराबरी से समझ सकें, ऐसी कार्यवाही तो कम से कम अभी शुरू होनी चाहिये । जो क्वैश्चन पूछे जाते हैं वह क्वैश्चन जितने अंग्रेजी में निकलते हैं उतने हिन्दी में निकलने चाहिएं ताकि हिन्दी वाले भी समझें और उनके बारे में सवालात कर सकें । इसलिए यह दिक्कत हमारे सामने बहुत बड़ी है । मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी में भी क्वैश्चन हों और हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही उसकी कार्यवाही हो और हिन्दी और अंग्रेजी में बराबरी से कार्यवाही होनी चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो बस कीजिये, आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री खादीवाला : बस आध मिनट में समाप्त किये देता हूं । हमारे देश में खनिज पदार्थों---तेल, पेट्रोल आदि के सम्बन्ध में बहुत हो-हल्ला है । इसका बहुत प्रचार हुआ है कि हमारे देश में पेट्रोल बहुत जल्दी निकल रहा है तो यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और स्वागत योग्य है कि पेट्रोल देश में ही निकलने से देश की काफी सम्पति हम बचा सकेंगे और इस वास्ते पेट्रोल को जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयत्न होना चाहिए ।

श्रीमती मिनीमाता (बलोदा बाजार–रक्षित–अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने खड़ी हुई हूं और उसके लिए आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार मानती हूं ।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में तृतीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई में इस्पात उत्पादन को दुगना करने की चर्चा की है । इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे देश के उद्योग की उन्नति होगी तथा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी । किन्तु यह दुःख की बात है कि उत्पादन में वृद्धि की व्यवस्था करते समय, मजदूरों की दशा को ध्यान में नहीं रक्खा गया है । मैं इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि भिलाई में इस समय भी स्थानीय मजदूरों से अधिक महत्व, बाहरी मजदूरों को दिया जा रहा है । बाहरी लोग ठेकेदार बन कर मजदूरों को धोखा देते हैं । यह तो ठीक है कि भिलाई से हमारे देश में लोहे का उत्पादन दुगना होगा और उसका लाभ राष्ट्र को होगा लेकिन मजदूरों का आज जो शोषण हो रहा है, और मजदूरों की जो भुखमरी है वह भयंकर रूप से सामने खड़ी है । यह खेद का विषय है कि छत्तीसगढ़ में बेकारों और मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी होने के बाद भी, मजदूर बाहर से लाकर भरती किये जा रहे हैं । इससे प्रदेश की बेकारी की समस्या और भी बढ़ गयी है और इसको लेकर प्रदेश की जनता में गहरा असन्तोष है । समय रहते, यदि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो यह एक भयंकर रूप धारण कर लेगी । यह भी ध्यान देने की बात है कि भिलाई के अधिकारियों का व्यवहार मजदूरों के साथ बहुत बुरा है और मजदूर जानवरों से भी बदतर हालत में रह रहे हैं ।

हमारे वहां का जो स्थानीय पुलिस विभाग है वह तो बिलकुल जनता और मजदूरों के प्रति उपेक्षा बरतता है और उनका कोई खयाल नहीं करता । भ्रष्टाचार वहां पुलिस डिपार्टमेंट में इतना बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं है । भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ वालों के लिए उस एरिया में बसने वालों के लिए पाकिस्तान के बराबर हो गया है । वहां के स्थानीय लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है इस बात का हमको दुःख है ।

राष्ट्रपति महोदय के भाषण में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की चर्चा हुई है तथा राष्ट्रपति महोदय ने खाद्यान्न की पैदावार और अधिक बढ़ाने की अपील की है पर यह ध्यान देने की बात है कि पैदा-वार बढ़ने के बाद भी चीजों की कीमतें कम नहीं हुई हैं। महंगाई की समस्या समूचे देश में फैली हुई है। राष्ट्र के हित के लिए उपज बढ़ाने वाला किसान आज भी बुरी हालत में रह रहा है क्योंकि उसे हर क्षेत्र में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों को सरकार जो तकावी वितरित करती है उसमें भी अंधेरगर्दी चल रही है और उसमें भी दलाल, घूसखोर और कई ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आधा पैसा काश्तकारों का आने-जाने में खर्च हो जाता है और केवल आधा पैसा ही किसानों को मिल पाता है। इसके अतिरिक्त पैसा जिस काम के लिए उसे मिलता भी है वह उस काम को नहीं कर पाता है और वे दलाल लोग पटवारी से मिल-जुल कर उनको ऐसा सिखला देते हैं कि वे अपने उस पैसे को दूसरे काम में भी ले सकते हैं और वे उससे कोई या तो जेवर बना लेंगे या लड़के लड़कियों की शादी कर देंगे और वह पैसा खेती के काम में नहीं लायेंगे। बैल और भैंस के खरीदने के लिए जो पैसा उनको मिलता है वह उससे बैल और भस न खरीद कर दूसरे कामों में खर्च कर डालते हैं और पटवारी लिख देता है कि बैल और भैंस लिया गया। पटवारी इस तरह से रिपोर्ट देकर उनको समझा देता है। उनको इतना गड़बड़ करने का अधिकार मिल गया है कि जिसका कोई कहना नहीं। यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसान नंगे और भूखे रह कर उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते, देश की उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि चीजों की कीमतों को बढ़ने से रोका जाय। छोटी सिंचाई योजनाओं को और अधिक बढ़ाया जाय और सहकारी बैंकों से उन्हें दो बार कर्ज दिया जाये।

अनुसूचित तथा आदिम जातियों की छात्राओं और छात्रों की शिक्षा की प्रगति के विषय में राष्ट्रपति महोदय ने संतोष प्रकट किया है। पर सच्चाई यह है कि जब तक इन छात्राओं को अनिवार्य शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती तब तक इस जाति का उत्थान नहीं हो सकता। यह ध्यान में रखने की बात है कि स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी ये जातियां अभी भी अशिक्षित है। यह आम शिकायत है कि छात्रों को छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिलती हैं।

दूसरी बात नौकरशाही की है। आप देखेंगे कि नौकरशाही में हम लोगों की तो उपेक्षा होती ही है। पांच बरस पहले जब हम जनरल इलेक्शन लड़े थे उन पांच बरसों में हम लोगों की उतनी उपेक्षा नहीं होती थी। अभी नौकरशाही के बीच में हमारी उपेक्षा होती है, यहां तक कि मंत्री महोदय की बात भी नहीं सुनी जाती। हम समझते हैं कि मंत्री महोदय को लिखें और यदि मंत्री महोदय लिखेंगे तो काम जल्द हो जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय लिखकर उनके पास भेजते हैं, तो वह नाक भौं सिकोड़ते हैं और जनता के काम की उपेक्षा करते हैं। इसकी भी कोई हद नहीं है। कहां तक हम इस दुःख को रोयें।

दूसरी बात है ग्राम पचायत की। यह बात मैं अपने अनुभव से कहती हूं। आप ग्राम पंचायतों का निर्माण तो हर जगह कर रहे हैं। पर ग्राम पंचायत में जिन लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए उनको उचित न्याय नहीं मिलता और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। जिसके पास पांच दस रुपया होता है वह ग्राम पंचायत के मेम्बरों

[श्रीमती मिनीमाता]

को थमा देता है और उसको न्याय मिल जाता है । लेकिन जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और जिसको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय नहीं मिल पाता ।

अब मैं कुछ ग्राम उद्योगों, छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं । हर एक प्रान्त में शायद आपने ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं जहां विद्यार्थियों को साबुन बनाना, जूता बनाना आदि काम सिखाए जाते हैं । यह काम सीखने के बाद उद्योग को बढ़ाने के लिए उन लड़कों को ग्रांट मिलने का जो कायदा है, उसमें लड़के लिखते-लिखते थक जाते हैं मगर उनको ग्रांट नहीं मिल पाता । उनको पता नहीं कि कहां जाएं किससे उनको पैसा मिलेगा जिससे कि वह उद्योग को बढ़ावें । वह परीक्षा पास करने के बाद निठल्ले बैठे रहते हैं, उनको सर्विस में नहीं लिया जाता । उनसे कहा जाता है कि ग्रांट ले लीजिये और उद्योग को बढ़ाइए । लेकिन वह उद्योग को बढ़ावें कैसे ? हमारे यहां ऐसे बच्चे हैं जो छः-छः महीने तक शहर में उद्योग कार्यालय को जाते रहे हैं यहां तक कि उनके जूते फट गए, पर उनको कुछ नहीं मिला । यह तो छोटे उद्योगों का हाल है ।

इसके बाद मैं छोटी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं । हमारी सरकार बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर रही है । लेकिन देहात में यह महसूस किया जाता है कि जब तक छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और उनको ज्यादा नहीं बनाएंगे तब तक खाद्य के उत्पादन में बहुत कमी रहेगी । छोटी सिंचाई योजनाओं को ज्यादा बनाया जाए ताकि किसानों को सुविधा हो ।

Shri Jamal Khwaja (Aligarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, before I say something on the President's Address, I would like to make a humble submission about the time-limit for speakers. I submit that every Member of Parliament should be given a minimum quota of time for the whole five year period because there are many of us who have spoken only very few times. We do not get an opportunity. Not that I am anxious to speak on every occasion but there are certain occasions when I would like to have a full say and I submit that there should be a minimum quota of time.

Mr. Deputy-Speaker: If he is not a Member of any particular party, then I can allot him, not the minimum but something more than the minimum. But if he is a member of some regular party, he should consult his own whips. He should not have any reason for complaining against the Speaker. Now, he is losing time out of the fifteen minutes minimum that he has.

Shri Jamal Khwaja: In this brief time that is allowed it is naturally impossible for me or anybody else to cover the whole field much as I would like to. Therefore, I would confine myself to a very few topics. After hearing the brilliant speech of Shri Vajpayee who is indeed a very fine and eloquent speaker, I would like to say something about the India-China situation, and about Shri Vajpayee's distrust of the ability and the split personality of the Prime Minister etc., but I am afraid I have to pass over all those questions because I am one of the large number of people, the majority of this House as well as of the country, who have full faith and confidence, implicit faith and confidence in the ability, sincerity and the wisdom of the Prime Minister and of the Government as a whole to carry us towards success.

Coming to the internal situation, I would like to summarise my analysis of the situation as follows, and this

may be regarded as my main thesis. On the one hand, in the quantitative sphere, and I use it in a very broad sense, we are progressing and going ahead. There can be no two opinions about it. I have no time nor ability to give facts and figures, but anyone who goes through the President's Address or the relevant statistical information that is furnished from time to time by the Government would have to admit that statistically we are going ahead, industrially we are going ahead and making progress.

But the interesting thing is that side by side with that there is a sort of, what I might call, lethargy. We as a nation are not working so hard. I think there can be no two opinions about it. It is significant that the Prime Minister and our top leaders make this appeal to the country from time to time at various occasions, at such special occasions as the Independence Day or the Republic Day and many other occasions. This appeal is made to the country from time to time. Shall we not be just? Are we as a nation working so hard as the Germans, the Japanese or the Americans have done? Are we? I think we have not and we are not. And all of us recognise it.

The question arises, why is it so? Why is it that we lack that creative spirit, that urge, that enthusiasm? There must be some reason. It is no use my speaking like a Member of the Congress Party just to praise or a Member of the Opposition speaking like a Member of the Opposition Party just to discredit, blame or find fault. We must seriously, in all humility and earnestness, with intellectual honesty and impartiality probe into this question. Why is it we are not so? It would be the height of rashness to suppose that this by itself proves that there is something basically wrong with the policy of the Government. It is not so simple as that.

Hard and creative work follows from very many factors, and one of the most important is the attitude of the people, of the vast masses of people. We, as a nation, have certain attitudes for the last 2000 to 3000 years, and those attitudes have shaped our actions. I need hardly say that an individual or a group of people who suppose that everything is done by the will of God or everything is determined by God, or that poverty, disease or ignorance, or storms and such calamities are the results of the divine Providence, they are either a test of the patience of man or a divine visitation for his punishment, it is natural that individual or that group of people would never be able to work as hard as a man or a group of persons or a nation who believe in the scientific attitude, who hold that all these events are determined by natural causes which can be studied and the laws of which can be applied for controlling these physical factors. It is natural that these European countries adopt the scientific attitude and therefore, they work hard. They know that everything depends upon their individual efforts. A farmer there knows it, the common man knows it and he gets his things done; but not we. This is a very important factor, and I am sure that any thinking man who gives serious attention to this problem realises it, but I beg to submit that apart from this basic factor there is something else and that is what I wish to speak about in a very brief way.

Sir, in all humility, with all sincerity and without any desire to praise anybody, to praise the Government or to blame the Government, I would say—there can be no two opinions about it—that the basic policies, the first level policies of the Government are sound. We are forging ahead. By basic policies, I mean the basic ideology, the vision, which inspire the Government and most of all the head of the Government. That is a vision of which we can be proud. There are people who criticise him; there are people and many other intellectuals also and a group of brilliant people, well-meaning people, who are coming up and criticising the Government. They say—I am referring to the Swatantra party—that planning and socialism have been proved out-of-date,

[Shri Jamal Khwaja]

that in England the British Labour party has shifted from the concept of socialism. Such statements are made. The doyen of politicians, who resides in the South, recently said that planning and democracy are incompatible or some such thing. In all earnestness, I would say that all these criticisms reflect not a sound judgment, not a fluid or dynamic thinking. Some of the leaders of the Swatantra party have said that the Prime Minister himself is a quarter of a century out-of-date. They have been so angered by the cirticism which the Prime Minister made that the Swatantra party's thinking is governed by 19th century logic, that they came out with the retort that much change has been seen during the last 25 years or so and that the Prime Minister himself is out-of-date.

I would very humbly beg to state that this shows a lack of dynamic thinking, a lack of the fundamentals of planning, of democracy, and I would refer them to some of the top intellectuals, American and German, and others in whose writings the arguments that these people make are met and more than amply met. So, I have no doubt that the basic policies of the Government, our secular approach, our internationalism, our concept of planned economy as a combination of socialism and democracy, both, are sound. I mean to say that all the important things are all sound. But, Sir, what is wrong is that in our enthusiasm for progress, for a speedy realisation of our dreams, for a quick ushering in of the welfare State, and in our concentration upon the big things which are certainly being done in a big way, in a magnificent way, and which rightly draws the attention of the world, small things are neglected. People from other countries who come here and visit those places, those places of pilgrimage—the plants and all that—have rightly praised us. There is no question of just courtesy. They are sincerely convinced, and so am I. But in our great concern for these big things, the small things, the insignificant and apparently trivial things are being neglected.

I say this is natural. Anyone who is doing a big task will not have the time and the energy to attend to the smaller details. That is natural. Whatever the task, whether it is religion, whether it is philosophy, this is natural. For example a philosopher will deal with the broad problems of religion. He will not go into those detailed theories, for that would become theology. A statesman has to deal with certain broad issues and not go into the details. So, this is natural. But, at the same time, I would submit that this is not wise for us, because we must not forget the fact that the people, the common people, do not realise the significance of these big things. They do not realise what is meant by the essential strength of the economy and self-sufficiency in these heavy industries and such things. They do not have the patience and they do not have the vision. For example, from the point of view of economy and self-sufficiency, say self-sufficiency in making steel is much more important. Or, self-sufficiency in the manufacture of locomotives is much important. From the point of view of the traveller and the ordinary passenger, a cushion seat or a fan and provision of running water in the train are far more important; he does not understand all the details, the mechanics, the foundation of the economy and all these things. Therefore, it becomes important from the point of view of the common man that attention should be paid to these things. This would be important in any country anywhere, but especially in a democracy it is very important, because what is called 'endurance threshold' in a democracy is lower than in a dictatorship. In a country like Russia, on account of the great respect in which their leaders like Stalin and others were held and also on account of its being a totalitarian country, it could be imposed. But in a democracy, the endurance threshold

is low. So, in the interest of our own country and in the interest of democracy, we should pay greater attention to this fact.

What should we do about it? What does it boil down to? I do not want this remark of mine to be interpreted as favouring consumer industry and opposed to heavy industry. That is an economic question. I think our planners and the Government have very rightly arrived at a compromise, a middle path. That problem has been solved for us. We are not following the way of Russia or any other country. We are following the Indian way of the golden mean. So, it is not an ideological difficulty I am raising, but a practical difficulty. In spite of the soundness of our vision and approach, because here are difficulties in administration and a number of other things, because the minor difficulties of the common man are not met, he is frustrated. Therefore, it is necessary for our top leaders to raise this problem, to appeal to them to work hard and they have to give the example of Germany, Japan or Russia.

I do not know how much time has been left to me. But in the limited time I have to.

Mr. Deputy-Speaker: He may take two minutes more.

Shri Jamal Khwaja: I am not eager to speak. There are other ways of being heard. I propose to write on these matters. Apart from the streamlining of the administrative machinery, I have got a few suggestions. It is useless to appeal to our clerks and other junior officers unless the scientific approach is adopted. The conditions of work in some of the Government offices are very undesirable. I have seen offices which are very dark with only a 25 watts bulb burning. I was surprised the people working there for a number of years did not lose their eye-sight, become blind. These things can be rectified without much expenditure. The Pay Commission went into the question of better salaries, etc. Our resources are limited and we may not be able to do much in those respects. But steps which do not require any great expenditure of money should certainly be carried out.

We cannot increase the salary of the clerks or other subordinate officers, but here again, we can give psychological awards. We might have a clerk's medal for the most efficient clerk, just like the police medal, so that he will be encouraged It does not cost anything to the exchequer. The most important thing in this connection is the question of human touch. The Home Minister has spoken on this several times, but do we understand what is meant by 'human touch'? I would have liked to go into this subject, because it is connected with psychology and I am a student of psychology. I would suggest that our officers and those who have to deal with men should be required to study the principles of social psychology. Just as our officers are asked to study languages—they are required to study the languages of the region in which they work and in the military also there are departmental tests and so on—all of them. whether it is a petty clerk or Secretary. (*An Hon. Member*: or a Minister) yes, certainly, or a Minister, should be asked to learn social psychology.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): They have no text-books.

Shri Jamal Khwaja: Sir, if you will permit me, I will skip over a large number of things and refer . . .

Mr. Deputy-Speaker: As he took time on big things, so he could not attend to smaller things.

Shri Jamal Khwaja: If you give me two minutes, I will finish.

Mr. Deputy-Speaker: All right.

Shri Jamal Khwaja: I will, very briefly, make a few observations about

[Shri Jamal Khwaja]

the problem of corruption, which was discussed in the other House and which is also being mentioned here. There is hardly any need of evidence for the conclusion that there is corruption, so far as the lower levels are concerned. As for the corruption alleged at the higher levels, it is obvious that we are not perfect. But I feel one thing, and that is, we are normal as compared to other countries of the world, barring a few countries like UK, and Sweden etc. Of course, there is room for improvement and it should be done, but it should be done in the proper way.

I do not think it is wise to cut an apple by a sword. If you want to cut an apple, you have to use a knife. But the knife must be sharp. I think the machinery which we have in the country at the moment is quite sufficient, provided it is put to use. There are some difficulties and there are delays. I have enough personal experience, and I would have liked to refer to them without mentioning names, but there is no time. So, I would submit: let us not take the sword to cut an apple; let us take a knife. But let us sharpen it and put it to proper use. But it cannot be done unless we first believe and remember and say that we shall not tackle the problem: by the spoon of love; we shall tackle it by the knife of justice. For that, the inspiration must come from the person sitting on that bench. It is only one man who can do the job; no one else can do it.

Shri Braj Raj Singh: He is not prepared to do it.

Shri Jamal Khwaja: He is. It is the knife of justice that will solve our problems, and I am sure they will be tackled in the right way.

Mr. Deputy-Speaker: I could accommodate only one person—either Shri Patnaik or Shri Brajesh.

Shri U. C. Patnaik (Ganjam): I am leaving Delhi tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: All right, Shri Patnaik.

Shri U. C. Patnaik: Mr. Deputy-Speaker, in moving my amendments Nos. 172 to 180 and 208 I beg to state that certain matters of importance raised or omitted in the President's Address disclose differences in approach between the *de jure* head of Government and the *de facto* head and I feel that there should be some clarification relating to article 53 of the Constitution. Although it is ten years since the Constitution came into force, I have to raise this constitutional question today because of those possible differences. Before I proceed with the points at issue, I would just read certain portions from article 53, wherein it is laid down that the President is the head of the civil administration as well as the supreme commander of the defence forces. It is stated:

> "Nothing in this article shall— ....prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President."

The powers of Supreme Command of the Defence Forces are vested in the President and are to be exercised by him as shall be regulated by law. I submit that during the last ten years there has been nothing in our legislative proceedings to clarify either aspects of the President's power and there has been no law to regulate his powers as Supreme Commander, nor any law to take away some of his powers and vest them on other authoties. I bring this point to the notice of the House because certain differences of approach have been noticed during recent days.

Firstly, there have been reports in the Press which have not been contradicted either by the President's Secretariat or by the Cabinet Secretariat. The President, according to those reports has been very much worried about the existence of corruption in the country and has written

to the hon. Prime Minister to see that measures are taken to prevent the same or to put it down. There has been no contradiction of this Press statement which has been very widely publicised. So we have to take it that the President must have made some such request to the Hon. Prime Minister. But then while preparing the "brief" that has been omitted so that there is no reference in his Address to the existing corruption and to the paramount necessity of checking it. That is a very important point because any suggestion from the President should be treated with greater respect than a scrap of paper. It having been publicised in the Press that the President has made such an appeal to the hon. Prime Minister, the absence of a reference to that corruption and to the necessity of checking it from the Address shows that that portion has been omitted for some reason or other.

Shri Achar (Mangalore): On a point of order, Sir.

Shri U. C. Patnaik: I am not yielding because the time at my disposal.....

Mr. Deputy-Speaker: But if there is a point of order, I have to hear that first.

Shri Achar: I would like to submit that the hon. Member is criticising the President.

Shri U. C. Patnaik: I am not.

Shri Achar: He is saying that the President has written a letter to the hon. Prime Minister stating that there is corruption and he is feeling that there is corruption, but still in his Address he has not mentioned it. That is to say, he is actually criticising the President by saying that he has not mentioned things which he ought to mention.

Mr. Deputy-Speaker: But when he says that something has not been mentioned, he only means that the Government has not advised the President to mention that. It is the Address which has been prepared by the Government. The President has nothing to do with it.

Shri Achar: I would submit with all respect that it would amount to finding fault with the President for not mentioning things he ought to have mentioned. That is the nature of his remarks.

Mr. Deputy-Speaker: No, I do not think so..... (*Interruption*). Should these rulings come from all sides or should I give it? When it is said that such-and-such thing has been said in the Address or when it is said that such-and-such thing has not been mentioned in the Address, we mean to criticise the Government which has advised or prepared that Address or has asked the President to put in this thing or omit that thing. It is really the preparation of the Government. The President is only to act on that advice. Therefore it should not be taken so technically when he says that in the Address the President has not mentioned it. He means to say that the Government has not advised the President to enter such-and-such thing. It is always like that.

Shri U. C. Patnaik: In the context of corruption I would refer this House to the report which one Shri Gorwala, a senior officer of the Government, was asked to make to the Planning Commission in 1950.

Mr. Deputy-Speaker: There is one thing that struck me. How did he get this information that the President has written to the hon. Prime Minister?

Shri U. C. Patnaik: That is the newspaper report.

Mr. Deputy-Speaker: It may not be true.

Shri U. C. Patnaik: I do concede that it may not be true.

Mr. Deputy-Speaker: If the Press makes a conjecture or a guess, we

[Mr. Deputy-Speaker]

should not rely on that. Ordinarily if something has been written by the President that would remain a secret.

Shri Khadilkar *rose—*

Shri U. C. Patnaik: I submit that that allegation was made in the Press and has not been contradicted. It was very widely reported and it has not been contradicted so far.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member would kindly resume his seat.

Shri Khadilkar (Ahmednagar): On a point of information. As you have rightly observed, the authenticity of the letter was not directly established, but it is indirectly, by implication, established when the hon. Prime Minister answered questions based on that news. I was one of the questioners. So, by implication the authenticity of the latter is established.

Mr. Deputy-Speaker: What did the Prime Minister say, that he had received it?

Shri Khadilkar: No.

Mr. Deputy-Speaker: He might be receiving any number of letters from the President, there might be correspondence going on. He might have admitted that he received a letter from the President. That might contain many things, that we do not know. If the Prime Minister had said that the President had mentioned that fact, or was of that opinion, then that is a different thing. He has not said that. Therefore, we cannot refer to it or draw from it and argue upon it that the President had written a letter to the Prime Minister in which he had given that information. That should be avoided. Why should we use that?

Shri U. C. Patnaik: I submit to your ruling, Sir, but I would only submit in addition that there has been no contradiction of that report.

Mr. Deputy-Speaker: It is not necessary.

Shri Kalika Singh (Azamgarh): His reference to the President's letter may be expunged.

Shri U. C. Patnaik: Then I proceed to another point, that is to Shri Gorwala's report of 1950. It was not a private report, but a report made at the instance of the Planning Commission to ensure greater efficiency in the services. In that report from page 12 onwards there is a chapter which shows how corruption creates an adverse effect on the popular mind and how it is to be checked. He has referred to various reports, various committees and various countries, and the steps to be taken to check corruption. One of them was appointment of a tribunal. I need not go into details because it is all there in the report, but what has happened to the report? It has been consigend to oblivion. Though it was made as early as 1950 no action was taken on it. He became a *persona non grata.* In these times when every retired officer is going to cushy job as an Ambassador or Governor,....

Mr. Deputy-Speaker: Is this a representation on his behalf then?

Shri U. C. Patnaik: No, Sir. I am simply referring to his report to the Planning Commission.

There was a report in the newspapers last year from London about a high dignitary of India being involved in certain deals, in the purchase of defence material. You will remember, Sir, that for the last so many years the Auditor-General has been complaining about the expenditure of hundreds of crores every year in the purchase of derelict stores from the U.K. and other countries, in the purchase of obsolete and obsolescent material, dud ammunition and other things. There have been criticisms not from private individuals, but from the Auditor-General under his statutory powers and from the

Public Accounts Committee of Parliament. We are told that out of deference to public opinion, certain suits were filed in London against these bogus firms with £1 or £100 share capital. We were told more than a year ago in an article that appeared in the press from London that a certain defendant in that suit who had become insolvent had pleaded that a very high dignitary of India was also involved, was one of the shareholders, was one of the partners in that firm.

Shri Tyagi: Where is that article?

Shri U. C. Patnaik: I do not know whether any such dignitary was involved or not, but that is the news given by Shri Kabadi in the press, and it has not been contradicted. I do not mean X or Y or Z. The public is confused because we do not know whether he is a senior officer, a politician or one of the other great men in the country, who he is? Such an allegation appeared in the press, and it seems it is not a bogus allegation because some defendant in the suit we filed against Sir James Marshal Corwa'il & Co., Lee, Shearle and others, made an assertion in court that a "high dignitary' of India was his partner.

We do not know whether it is true, but we would expect Government to make enquiries and to find out who that high dignitary is. Shri C. D. Deshmukh has been asked for names. I am submitting with what little we have done, with what little we had studied of these transactions in England and other countries, with what little we in certain committees had found out about bogus transactions whereby India purchased dud weapons, whereby India purchased bad material, obsolete and obsolescent, that those things were reported, cases have been lodged, and after the cases have been lodged, a defendant makes an assertion in a court of law that some high dignitary of India was a partner. We want Government and the Prime Minister to try to find out who that high dignitary is.

Mr. Deputy-Speaker: What has the court said about that statement?

Shri U. C. Patnaik: We do not know. That was the only report that came out in the papers. But, whatever that may be, my submission is this. Has it been enquired into?

Mr. Deputy-Speaker: If the court had said that that was a lie, then should Government institute another proceedings?

Shri U. C. Patnaik: I do not know. I do not go so far. The case is going on, and the report in that newspaper was that some sort of averment or some sort of allegation was made that the Government of India were prepared to withdraw their claim. We do not know at what stage it is. We put questions in this House, but we could not get a definite reply.

Shri Tyagi: The Government of India were never wanting to withdraw the case.

Shri Braj Raj Singh: With what authority does Shri Tyagi say all this?

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): He is perfectly justified in saying so, because there is no Cabinet Minister present here now during the discussion.

Shri U. C. Patnaik: According to Government Conduct Rules, it has been laid down that every Government servant shall disclose the property standing in his own name and in the names of his near relations and dependants, property in his possession or in his relations' possession, property in the banklockers or in any other form. Every Government servant has to submit a statement of his assets and properties. I leave it to the consideration of the Government of India whether they would like to enforce some such rule in relation to the Ministers and other high dignitaries also, with a view to prevent people from making any such remarks.

[Shri U. C. Patnaik]

Then, there is another thing that was reported in the press recently. We have in the President's address a statement to the effect that a Bill is being introduced shortly for the abolition of double-member constituencies. I do not go into the correctness or otherwise of that proposal, but what I would submit is that shortly after the President's Address, I think, two or three days thereafter, there appeared a news item that at a meeting of the ruling party, a statement was made by certain high dignitaries that there would not be any such Bill forthcoming.

Shri Tyagi: I hope he was not a partner.

Shri U. C. Patnaik: No, no.

If that be so, then I would only submit that the President was not properly briefed when he drafted the Address, for, you know the circumstances in which the Address is given, and the briefing and checking up by the Ministries, and the President had been put in an embarrassig position.

Mr. Deputy-Speaker: Would the hon. Member depend entirely on something that was said by a witness in a case that was pending elsewhere, for one of his statements, on what happened at the meeting of a political party, for a second statement of his, and on what appeared in the press, for a third statement of his, or has he anything more with which to satisfy us?

Shri U. C. Patnaik: I have nothing more. But these circumstances make us feel that there should be some sort of definition of article 53.

Mr. Deputy-Speaker: If I am not disclosing anything secret, it should not be taken as if the President had not been properly briefed. The only news item that has appeared is that during this Session, this Bill might not be taken up. That does not mean that it will never be taken up, or that it has been stopped altogether. It is for Government to allot priorities and see what legislation they can bring forward during this Session or they might like to bring forward. Why should we attach so much importance to it that it can be criticised afterwards?

Shri Braj Raj Singh: It was given out in the Press that the Bill 'shall be taken up in this session'.

Shri Tyagi: With your permission, may I clarify the position of the Party? The question was raised in the Party. (*Interruptions*). My hon. friend has referred to the ruling Party. It was explained that this Bill was only mentioned in the list of Bills going to be considered and that it would be open to Parliament and the Members to decide as to whether they agreed with it or not. It was only casually mentioned in the Address to give the public an idea of the bills that were going to be discussed. That is all.

Shri U. C. Patnaik: In conclusion, I have only one point, and that is about our position regarding China. I would submit that when people say that 'not a blade of grass will grow' or that there are 'administered areas and non-administered areas', there is a sort of suspicion growing in the country that we are likely to surrender certain positions or certain claims. Therefore, in view of the strong position taken up by the President in his Address, I would submit that we should take advantage of the short space of time that we have before the weather clears up, and reorganise our defences, build up our civilian defences and keep up the morale of the civilian population to see that we strengthen ourselves in every way.

श्री राम (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में दो बातों की ओर विशेष कर देशवासियों का ध्यान दिलाया है। उन्होंने अभिभाषण के पेज ५ के पैरा २५ में अनाजों

के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता के बारे में जो कहा है मैं उसे सदन में पढ़ देना चाहता हूं :—

"हर वर्ष हमें खाने के लिये और संचय के लिये भारी मात्रा में अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा के हमारे क्षीण साधनों पर बहुत दबाव पड़ता है और जो हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्रतिकूल है ।"

ऐसा उन्होंने कहा है लेकिन इसके पीछे हमारी कितनी खराब हालत हो रही है और कितना नुकसान हो रहा है उसको सदन के सामने नहीं रक्खा गया है । मैं उस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । सन् १९४८ से १९५८ तक यानी दस साल में हम को ११६० करोड़ रुपये का खाद्याल इम्पोर्ट करना पड़ा । हर साल औन एन एव्रज ११५ करोड़ रुपये का अनाज इम्पोर्ट करना पड़ता है । हर साल २६ लाख टन अनाज इम्पोर्ट करना पड़ता है । दस साल के बाद भी हमारी हालत ऐसी है । इसकी ओर जहां राष्ट्रपति ने अपने भाषण में संकेत किया है वहां इस बुरी हालत में से हम कैसे बाहर निकलें इसके वास्ते सदन को कोई राह नहीं दिखलाई है ।

हम को हर साल २६ लाख की यानी ५० मिलियन टन की जरूरत पड़ती है उसमें २६ लाख माने केवल ढाई परसेंट की कमी पड़ती है दस साल में । यह कमी ऐसी चली आती है । ५ परसंट की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हुए भी हम उस कमी को पूरा नहीं कर सके, आखिर इसका क्या कारण है ?

राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए इस बात की आवश्यकता को स्वीकार किया है कि प्रशासन की योग्यता भी उसी कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना लाई जाये ताकि सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाये और जनशक्ति तथा समय का अपव्यय न हो । ऐसा उन्होंने बतलाया । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम इसी बात की कमी अपने प्रशासन में देख रहे हैं । आज भी जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में बुराइयां हैं उनसे हम ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं । हम अपने देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि लैंड रिफार्म्स किये जायें । इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाये जायें और किसानों को फैसिलाइजर्स दिये जायें वह सब तो ठीक है लेकिन आज जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में बुराई और भष्टाचार है उसके कारण हालत यह है कि हालांकि सिंदरी फैक्टरी से अमोनियम सल्फेट का एक बोरा ३९ रुपये का मिलना चाहिये लेकिन हर साल हर मौसम में आंध्र प्रदेश में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हमको कोटा सीधा गवर्नमेंट से नहीं मिलता है हालांकि उसकी कोई कमी नहीं है । तो भी वह ३२९ रुपये का बोरा ६०, ७० रुपये पर कलकत्ते से चोर बाजार से आ रहा है । सैकड़ों टन हमको हमेशा मिलता है लेकिन किसानों को वह उचित दाम पर और सीलिंग प्राइस पर नहीं मिलता है । आखिर यह जो करप्शन और गड़बड़ इस सिलसिले में चल रही है और अन्य क्षेत्रों में चल रही है उसको रोकने के लिये हम क्या कारगर उपाय कर रहे हैं ? इन खराबियों के रहते हम किसानों को कैसे जोश दिला सकते हैं कि वह जी जान से अनाज की पैदावार बढ़ाने में जुट जायें । आज जरूरत इस बात की है कि इन खराबियों को मिटाने की हमें कोशिश करनी चाहिये ।

हम देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा अपने हर वार्षिक सेशनों में और खाली नागपुर कांग्रेस में ही नहीं, लैंड रिफार्म्स करने की बात की जाती है लेकिन केरल राज्य के अलावा कहीं दूसरी जगह लैंड रिफार्म्स के लिये कानून नहीं पास किया गया और अगर कहीं उनके लिये

[श्री राममं]

कानून बनाया भी गया तो वह कानून किसी स्टेट में अमल में नहीं आया ।

हम इतनी गैर जिम्मेदारी से काम लेते हैं कि ११६० करोड़ के फौरेन एक्सचेंज का दस साल में नुकसान करते हुए हम इम्पोर्ट करते हैं लेकिन हम अपनी जमीन को खेती योग्य बनाने और मनुष्य शक्ति को इस्तेमाल में लाने के लिये काफी कोशिश नहीं करते हैं । यह बहुत दुःख की बात है और इस ओर सरकार का तुरन्त ध्यान जाना चाहिये । मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ इस तरह से यहां पर भाषण किये जिससे प्रकट होता था कि हिन्दुस्तान की बड़ी तरक्की हो रही है और वह हर दिशा में उन्नतिशील है । म भी मानता हूं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में, बड़े बड़े प्राजेक्ट्स बनाने में थोड़ी तरक्की हुई लेकिन उसी के साथ साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे अन्य उत्पादन के काम में इतना कुछ काम नहीं हो रहा है । इंडस्ट्रीज जरूर हमने खोली हैं लेकिन हम मेजोरिटी लोगों को नेशनल प्रीडेक्शन में नहीं ला सके इसका कारण यह है कि काफी तादाद में हमारे देश में लोग बेकार बैठे हैं । देहातों में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको कि काम नहीं मिलता है और यह हालत तब है जब कि देश में लाखों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है और उसको तोड़ कर खेती योग्य बनाया जा सकता है और उनको काम दिया जा सकता है और कृषि की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है । यह तो ठीक है कि सरकार पालिसी बनाती है कि बेकारों को काम दिया जाये, भूमिहीनों को जमीन दी जाये लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन में जिन लोगों पर इन पालिसियों को अमल में लाने की जिम्मेदारी है वह उसको निबाहते नहीं हैं बल्कि उसके विरुद्ध आचरण करते हैं और इसी का कारण यह है कि आज हमारी खराब हालत बनी हुई है । यह हम सभी स्टेट्स में देखते हैं । वहां एग्रीकल्चर का काम बहुत हो रहा है । लेकिन हमारे सामने एक ही सहारा है । कोआपरेटिव फार्मिंग के अलावा हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते लेकिन उसको अभी देश में शुरू नहीं किया गया और उसका फायदा नहीं हो रहा है । आज हम ऐसे नारे सुनते हैं कि अगर गहकारी खेती बढ़ेगी तो भारत में किसानों की स्लेवरी हो जायेगी ।

17 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दो तीन मिनट में खत्म करना चाहेंगे या कल जारी रखना चाहेंगे ।

श्री राममं : मैं कल को जारी रखना चाहूंगा ।

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow. The House now stands adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 18th February, 1960.

17·1 hrs.

The Lok Sabha, then, adjourned till Eleven of the Clock on Thursday February 18, 1960/*Magha* 29, 1881 (*Saka*).